www.bharatsamvad.live

R.N.I.No- MAHHIN/2017/74173

सत्य का स्वर

भारत संवाद

मुंबई, प्रयागराज और लखनऊ से प्रकाशित

सोशल मीडिया पर भारत संवाद
https://x.com/BharatSamvad
www.facebook.com/bharatsamvad.in
www.youtube.com/@BharatSamvad-m3n
E-Paper bharatsamvad.live

मौसम
अधिकतम तापमान 35.c
28.c न्यूनतम तापमान

बाजार
सोना 95.770g
चांदी 78.800 kg

2 कर्तव्य पालन में अनदेखी का नतीजा, कोर्ट को सुनवाई की समयसीमा निर्धारित करने का अधिकार

एडीएम ने किसान बनकर पकड़ा अवैध गेहूं से भरा ट्र 04

वर्ष :08 | अंक :296 | मुंबई ,शुक्रवार , 18 अप्रैल, 2025 | पृष्ठ : 06 | मूल्य : 2: 00 रुपए

संक्षिप्त समाचार

विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लिथुआनिया की रहने वाली महिला आगरा किला देखने गई थी। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बुधवार को हुई, जब महिला ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण कर रही थी। इस दौरान एक अन्य पर्यटक ने कथित तौर पर उसे अनुचित तरीके से छुआ। घटना के बाद पर्यटन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सहायक पुलिस आयुक्त (ताज सुरक्षा) सैयद अरीब अहमद ने कहा, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा और पूछताछ करने के बाद, हमने आरोपी मिजान को गिरफ्तार कर लिया, जो हरियाणा के मेवात का पर्यटक है। वह भी किला देखने आया था। अहमद ने कहा कि मिजान को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

पंजाब में यूट्यूबर के घर पर हथगोला फेंकने के मामले में सेना का एक जवान गिरफ्तार

जालंधर के एक यूट्यूबर के घर पर पिछले महीने हथगोला फेंकने की घटना के सिलसिले में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में तैनात सेना के जवान सुखचरण सिंह को एक आरोपी को हथगोला फेंकने का ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर रोजर संधू के आवास पर 15-16 मार्च की दरमियानी रात को एक हथगोला फेंका गया था हालांकि यह फटा नहीं था। पुलिस ने कहा कि उसने मामले में जवान की भूमिका के बारे में सेना के अधिकारियों को अवगत करा दिया है। पुलिस ने बताया कि जालंधर की एक अदालत ने सेना के जवान को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है तथा मामले की जांच जारी है। घटना के बाद पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक का इस्तेमाल करने के लिए यूट्यूबर के आवास पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। घटना के सिलसिले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं :उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़

जज 'सुपर संसद' की तरह काम कर रहे, अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया

जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और पूछा कि क्या न्यायाधीश सुपर-संसद के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है?

एजेंसी

उन्होंने कहा, इसके बाद, सौभाग्य से, सार्वजनिक डोमेन में, हमें एक आधिकारिक स्रोत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इनपुट मिला। और इनपुट ने दोषी होने का संकेत दिया। इनपुट से यह संदेह नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुछ जांच की आवश्यकता है। अब राष्ट्र सांस रोककर इंतजार कर रहा है। राष्ट्र बेचैन है क्योंकि हमारी एक संस्था, जिसे लोग हमेशा सर्वोच्च सम्मान और आदर के साथ देखते हैं, उसे कटघरे में खड़ा किया गया है। उन्होंने रेखांकित किया कि न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के अभियान के दौरान नकदी बरामद होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और कहा कि देश में किसी के भी खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करना है तो विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है

नयी दिल्ली : उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की असीमित स्वतंत्रता पर सवाल करते हुए गुरुवार को कहा कि कोई शक्ति किसी भी आधार पर राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकती। श्री धनखड़ ने उप राष्ट्रपति निवास पर राज्यसभा के छठे बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं बनायी जा सकती कि कोई राष्ट्रपति को निर्देश दे सके। न्यायपालिका की भूमिका परामर्श की है। उन्होंने कहा, परामर्श सहमति नहीं है, परामर्श केवल परामर्श है। उप राष्ट्रपति का यह वक्तव्य उच्चतम न्यायालय के हाल के उस निर्णय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे विधेयकों पर अधिकतम तीन महीने के भीतर फैसला करना होगा। धनखड़ ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है।

राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। यह शपथ केवल राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल लेते हैं। हर कोई, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, ये सभी संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। उन्होंने कहा, संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान का संरक्षण करने के लिए, वह भारत के राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर की शपथ है। उन्होंने कहा कि हाल के न्यायालय के एक निर्णय द्वारा राष्ट्रपति को एक निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा का निगहबान सीआरपीएफ, देश से 2026 तक खत्म कर देंगे नक्सलवाद: अमित शाह

देश के अलग-अलग हिस्सों में मनेगा सीआरपीएफ का स्थापना दिवस

नीमच में बोले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, हमारा सीआरपीएफ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल. 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे.

एजेंसी

नीमच: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नीमच में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर शहीद स्थल पहुंचे और सीआरपीएफ के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि, "सीआरपीएफ के सभी शहीद जवानों के परिवारों को मैं कहना चाहता हूं कि देश सशक्त और समृद्ध हो रहा है, उसमें आपके परिवार का योगदान अनमोल है. जब भी देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गाथा लिखी जाएगी, उसमें आपके परिवार का योगदान हमेशा याद किया जाएगा."

सीआरपीएफ ने हर हमलों को नाकाम किया

अमित शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सीआरपीएफ के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. हमारे वीर जवानों के उत्थान, सम्मान तथा उनके परिवारजनों के लिए कई सुविधाओं को मुहैया कराने का कार्य किया है. संसद भवन पर हमला हो या रामजन्मभूमि की रक्षा की बात हो, सीआरपीएफ ने हर हमलों को नाकाम किया है."देश को नक्सलमुक्त बनाने में हमारे कोबरा बटालियन के जवान अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं. 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा. देश की सुरक्षा के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया, पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करना हो या नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में हमारे सीआरपीएफ जवानों का योगदान महत्वपूर्ण है."

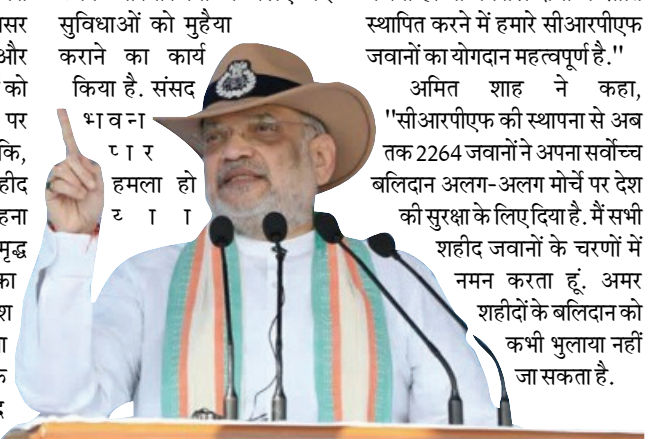

अमित शाह ने कहा, "सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग-अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है. मैं सभी शहीद जवानों के चरणों में नमन करता हूं. अमर शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

जिनका नाम स्कैम में नहीं, नई प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ा सकते हैं

बंगाल के 'बेदाग' शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मई तक नया भर्ती अभियान शुरू करने और 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, हम वर्तमान आवेदन में प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह कक्षा 11 और कक्षा 12 के सहायक शिक्षकों से संबंधित है।

एजेंसी

नयी दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले बेदाग सहायक शिक्षक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मई तक नया भर्ती अभियान शुरू करने और 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, हम वर्तमान आवेदन में प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह कक्षा क- और कक्षा क-कक के सहायक शिक्षकों से संबंधित है। यह आदेश केवल सहायक अध्यापकों पर लागू होगा, क्योंकि पीठ ने कहा कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई थी। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने निष्कर्ष निकाला था कि विचाराधीन भर्ती प्रक्रिया में बुनियादी तौर पर खामियां थीं। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी ने नियुक्तियों की ईमानदारी को इस हद तक प्रभावित किया है कि उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया दूषित और दागी थी, जिससे नियुक्तियां अमान्य हो गईं।

बिहार में विपक्ष की बड़ी बैठक

तेजस्वी यादव बोले- विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत

राजद नेता ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री बिहार आते रहते हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में असली डबल इंजन है- अपराध और भ्रष्टाचार।

एजेंसी

बिहार चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई। यह बैठक ढाई घंटे तक चली। बिहार महागठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हालात पर आज महागठबंधन की पहली बैठक हुई। हमने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से जुड़े मामलों पर चर्चा की। हमने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से जुड़े मामलों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 सालों से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ बिहार के लोगों में काफी गुस्सा है। अपराध, बेरोजगारी और मजदूरों के पलायन में बिहार नंबर वन है। राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।राजद नेता ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री बिहार आते रहते हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में असली डबल इंजन है- अपराध और भ्रष्टाचार।

दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से की मुलाकात

वक्फ कानून को बताया ऐतिहासिक

दाऊदी बोहरा समुदाय ने आगे प्रधानमंत्री के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वे इस सोच के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे।

एजेंसी

दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी।

दाऊदी बोहरा समुदाय ने आगे प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वे इस सोच के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे।

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

नियुक्तियां रोकीं, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब; 5 मुख्य आपत्तियों पर होगी सुनवाई

केंद्र के जवाब का प्रत्युत्तर पांच दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा और सुनवाई मई में शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन केंद्र के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है कि संशोधित अधिनियम के तहत फिलहाल केंद्रीय वक्फ परिषद या वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

एजेंसी

नई दिल्ली , वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है।सरकार के जवाब के बाद याचिकाकताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं। उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को तीन निर्देश मानने होंगे।सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, '110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं हैं। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं।

कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से झटका...शिंदे की आलोचना मामले में अग्रिम जमानत याचिका रद्द

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है.

एजेंसी

चेन्नई: कॉमेडियन और अभिनेता कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में यूट्यूब पर आलोचना करने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को बंद कर दिया है.दरअसल, पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना-भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बने थे.

वार | नेशनल हेराल्ड केस में संबित पात्रा का गांधी परिवार पर वार

सोनिया और राहुल गांधी आधुनिक डकैत

एजेंसी

पात्रा ने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि आज से इस मामले को चोरी या भ्रष्टाचार मत कहिए, ये खुली डकैती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आधुनिक डकैत हैं। ये नेशनल हेराल्ड डकैती का मामला है।

नयी दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को 'जबरदस्त डकैती' करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 'आधुनिक डकैत' कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने इस सप्ताह मामले में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। पात्रा मे कहा कि क्या कोई राजनीतिक कंपनी किसी दूसरी संस्था को पैसा उधार दे सकती है? कांग्रेस पार्टी, जो चंदे पर निर्भर है, उसने बैंक की तरह यंग इंडियन और अखछ (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को कैसे पैसा उधार दिया? पात्रा ने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि आज से इस मामले को चोरी या भ्रष्टाचार मत कहिए, ये खुली डकैती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आधुनिक डकैत हैं। ये नेशनल हेराल्ड डकैती का मामला है। आरोप पत्र में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, अन्य व्यक्तियों और फर्मों का भी नाम है। मामले में बहस 25 अप्रैल को होगी। यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ दायर की गई शिकायत पर आधारित है। इससे पहले गौरव भाटिया ने एक तीखे संबोधन में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पर हमला बोला और उन्हें 'वंशानुगत भ्रष्ट' व्यक्ति करार दिया। यह बयान गुरुग्राम भूमि मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वाड्रा से पूछताछ के बीच आया है। मीडिया को संबोधित करते हुए भाटिया ने वाड्रा को 'भू-माफिया' करार दिया, जिन पर किसानों की जमीनों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप है। इसके अलावा, उन्होंने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड घोटाले, सोनिया गांधी को वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले से जोड़ते हुए उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। भाटिया ने कहा कि एक ईमानदार सरकार की ताकत क्या होती है, ये भारत में अब जनता को पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, किसानों से हड़पी गई जमीन को वापस लेकर किसानों को देंगे। जनता की गाढ़ी कमाई अगर नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाली है, उसकी एक-एक पाई वसूली जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का संकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से जो कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब उन्हें देना पड़ रहा है।

'चंदाचोर पार्टी से अब चंदाखोर पार्टी बन गई आप'

बीजेपी बोली- उसके नेताओं का चरित्र ही लूट, भ्रष्टाचार और झूठ

सचदेवा ने कहा कि सभी जानते हैं कि यह पार्टी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। इसे सिर्फ चोरी, कमीशन और रिश्वत लेना है। उन्होंने कहा कि कहा कि अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का चरित्र ही लूट, भ्रष्टाचार और झूठ है।

एजेंसी

नयी दिल्ली। आप नेता दुर्गेश पाठक के ठिकानों पर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो पैसा इकट्ठा हुआ था, वह गोवा चुनाव में चला गया। दुर्गेश पाठक एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने अपनी ही पार्टी के चंदे का पैसा चुराया है। इस पार्टी ने दस तरह की चोरी और घोटाले किए हैं,

लेकिन अपनी ही पार्टी का चंदा खाने वाले चंदा इकट्ठा करने वाले लोग ज्यादा चालाक निकले हैं, और इस समय यह जांच लगातार चल रही है। सचदेवा ने कहा कि सभी जानते हैं कि यह पार्टी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। इसे सिर्फ चोरी, कमीशन और रिश्वत लेना है। उन्होंने कहा कि कहा कि अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का चरित्र ही लूट, भ्रष्टाचार और झूठ है। इसी कड़ी को आगे बढाते हुए दुर्गेश पाठक ने अपने लूट और भ्रष्टाचार को छुपाते हुए एक और झूठ दिल्ली की जनता से छुपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में शराब घोटाले के माध्यम से पैसे इकट्ठा किया गया तो उस वक्त वह सारे पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया था और उस वक्त दुर्गेश पाठक ही गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रभारी बने थे।

सम्पादकीय

अदालत में वक्फ कानून पर सुनवाई, विरोध के बहाने हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना ही चाहिए लेकिन अंतरिम आदेश देने के पहले दोनों पक्षों के विचार सुनना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही संसद से पारित किसी कानून का सड़कों पर उतरकर हिंसक तरीके से विरोध करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित भी किया जाना चाहिए। तब तो और भी जब उस कानून पर सुनवाई हो रही हो।सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ कानून की सुनवाई करते हुए इस कानून के विरोध के बहाने हुई हिंसा पर चिंता तो जताई, लेकिन अच्छा होता कि वह केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहता। उसे वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों को सख्त संदेश देने के साथ ही राज्य सरकारों और विशेष रूप से बंगाल सरकार को निर्देश देने चाहिए थे कि इस हिंसा पर हर हाल में लगाम लगे।उसे इसका भी संज्ञान लेना चाहिए था कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून विरोधियों की भीषण हिंसा के चलते वहां के अनेक हिंदुओं को जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा है और इसका कोई ठिकाना नहीं कि वे अपने घरों को लौट सकेंगे या नहीं? उससे मुर्शिदाबाद की हिंसा पर ध्यान देने की अपेक्षा इसलिए थी, क्योंकि उसके समक्ष इसकी गुहार लगाई जा चुकी है।वक्फ कानून पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस कानून में कुछ सकारात्मक बदलावों का उल्लेख किया, वहीं उसके कुछ प्रविधानों पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को नोटिस भी जारी किया। कहना कठिन है कि इन सवालों के जवाब मिलने पर उसका दृष्टिकोण क्या होगा, लेकिन पहली ही सुनवाई के दौरान एक समय उसने अंतरिम आदेश पारित करने का जो संकेत दिया, उसकी आवश्यकता नहीं थी।वक्फ कानून पर पहले संयुक्त संसदीय समिति में व्यापक चर्चा हुई और फिर संसद के दोनों सदनों में। जिस कानून में महीनों की बहस के बाद संशोधन किए गए हों, उस पर अंतरिम आदेश जारी करने की जल्दबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए।यह ठीक है कि वक्फ कानून को लेकर 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें अधिकतर उसके विरोध में हैं, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि यह एक महत्वपूर्ण कानून है और उसके कुछ प्रविधानों में संशोधन आवश्यक हो गए थे। वक्फ कानून की संवैधानिकता की परख में हर्ज नहीं।सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन अंतरिम आदेश देने के पहले दोनों पक्षों के विचार सुनना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही संसद से पारित किसी कानून का सड़कों पर उतरकर हिंसक तरीके से विरोध करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित भी किया जाना चाहिए। तब तो और भी, जब उस कानून पर सुनवाई हो रही हो।पिछले कुछ समय से यह प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून का सड़कों पर उतरकर विरोध किया गया था।

आज का विचार

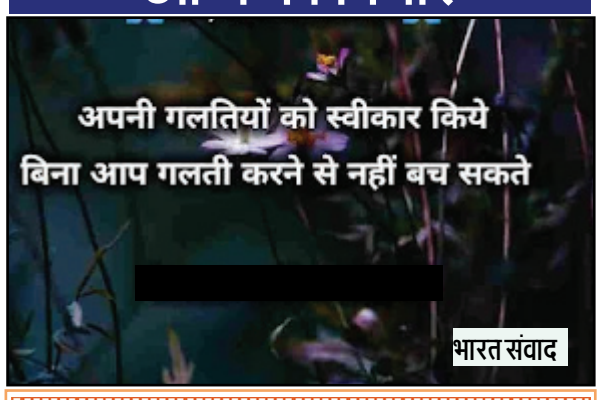

राशिफल

मेष राशि: आपके लिए किसी नये काम की शुरूआत करने के लिए अच्छा रहेगा. आप अपने खर्चों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी योजनाओं को बनाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ नई योजना की शुरूआत कर सकते हैं.

वृष राशि: आपके लिए ऊजार्वान रहने वाला है. आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. दान धर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी. आप अच्छे निवेश को करने की तैयारी कर सकते हैं. आपको अपने करीबियों का पूरा साथ मिलेगा.

मिथुन राशि: आपके लिए कार्यक्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है. आपको अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान देना होगा. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और धन धान्य में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपको अधिक समय देना होगा. आपको जीवनसाथी के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है.

कर्क राशि:आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है. सेवा क्षेत्र से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा. विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. आप अपने निजी मामलों में सहजता से आगे बढ़े, तो आपके लिए अच्छा रहेगा.

सिंह राशि: आपके लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप किसी से बहसबाजी में ना पड़े. सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता सता सकती है. आपके लंबे समय से रुके हुए काम गति पकडेंगे.

कन्या राशि: आपके लिए बहुत ही सोच विचारकर निर्णय लेने के लिए रहेगा. अपनों के साथ विश्वास बनाए रखेंगे. यदि आप किसी से कोई बात बोले, तो उसमें विनम्रता बनाए रखें. परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम पर अच्छा खासा धन खर्च होगा. आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है.

तुला राशि:आपके लिए साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है. आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि: आपके लिए किसी बजट को बनाकर चलने के लिए रहेगा. आप अपने मामलों में लापरवाही ना करें और यदि आपने किसी से धन उधार लिया, तो आपको उसे उतार पाने में मुश्किल होगी. आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़ें, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं.

धनु राशि: आपके लिए कला व कौशल में सुधार लेकर आएगा. रचनात्मक कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा. मित्रों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं.

मकर : सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है. आपको बड़ों की सोच पर चलना बेहतर रहेगा. घर परिवार में आप भौतिक वस्तुओं पर पूरा ध्यान देंगे. आपको कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है. विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है.

कुंभ राशि: आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए रहेगा. आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं और आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे.

मीन राशि: आपके लिए धन-धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है. आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे और आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से मेहमानों का आगमन लगा रहेगा. आप सभी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सफल रहेंगे. आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी. आप अपने परिजनों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे. परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने से आप प्रसन्न रहेंगे और संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे. आपको विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है.

ज्योतिष सेवा केन्द्र
ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री

कर्तव्य पालन में अनदेखी का नतीजा, कोर्ट को सुनवाई की समयसीमा निर्धारित करने का अधिकार

सुझाव यह भी है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना था कि यह अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरकारों को बचाने के लिए लागू होता है।

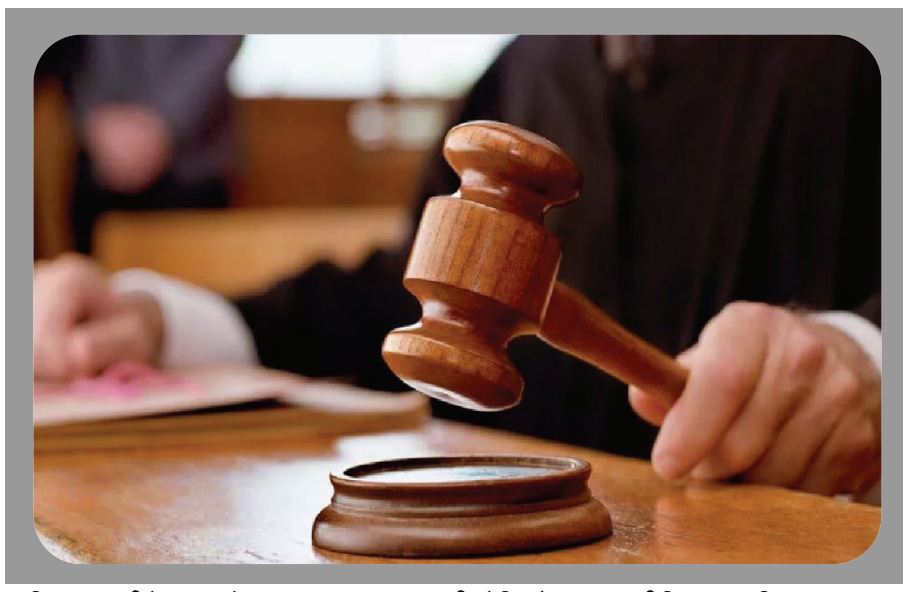

सर्वोच्च न्यायपीठ ने दलबदल की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा है कि इनसे जुड़े निर्णय में देरी से संविधान की दसवीं अनुसूची के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट को सुनवाई की समयसीमा निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय याचिकाओं के परिणाम नहीं निर्धारित कर सकता।यह निर्धारण सदन के सभापति करते हैं। कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा मामले (2020) सहित कई मामलों में निर्णय की समयसीमा निर्धारित करने की अपेक्षा की है। एक मामले (1992) में कहा कि कार्यवाही में देरी की स्थिति में न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। 1994 में रवि एस. नायक बनाम भारत संघ मामले में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर भी टिप्पणी की गई थी।इसी तरह कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में 10 विधेयकों को लंबे समय तक विचारार्थ रखने को लेकर राज्यपाल पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय की कोई समयसीमा नहीं है, पर कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूर करने का फैसला अनु. 142 की विशेष शक्तियों के अंतर्गत कर दिया।कोर्ट ने राष्ट्रपति की एवं अपनी शक्तियों का अलग-अलग उल्लेख किया है। दोनों आदरणीय हैं, मगर अधिकारों की तुलना विचारणीय है। प्रथमदृष्टया संविधान के दोनों प्रविधानों में टकराव दिखाई पड़ रहा है। यह उचित नहीं है। यदि संवैधानिक संस्थाएं ठीक से कर्तव्यपालन करें तो संवैधानिक राजव्यवस्था भी ठीक चलती है। कर्तव्यपालन न करें तो कठिनाइयां आती हैं।संसद और विधानमंडलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 102 एवं 191 में सदस्यों के लिए अनेक अयोग्यताएं निर्धारित हैं। संसद ने दलबदल विरोधी अधिनियम बनाया था। पिछली सदी के सातवें दशक में थोक के भाव दलबदल हो रहे थे। हरियाणा के एक नेता ने 1967 में एक दिन में तीन बार दलबदल किया था। तभी ह्यआया राम गया रामह्ल का मुहावरा चला। इसके बाद कई राज्यों में दल टूटकर सरकारें बनीं।जनतंत्र में दल विचार के आधार पर बनते हैं। विचार निष्ठा लोकप्रिय बनाती है। राजनीतिक दल व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं। वह जिस दल से निर्वाचित होता है उसे छोड़ देना मतदाता के साथ धोखाधड़ी एवं वैधानिक अनैतिकता है। 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में 404 कांग्रेसी सांसद थे।कहा जाता है कि उन्होंने दलबदल के भयवश 52वां संविधान संशोधन पारित करवाया था। यही संविधान की दसवीं अनुसूची है। इसमें दलीय सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के एक साथ दलबदल करना दलों का विलय माना गया था। अजीब है कि जो काम एक व्यक्ति करे तो पाप है। एक तिहाई करें तो पुण्य।अनेक राज्यों में दलबदलुओं को लाभ हुआ। वे रातोंरात मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों से लाभान्वित हुए। 91वें संविधान संशोधन द्वारा विलय की सुविधा में सख्ती आई। एक तिहाई की जगह दो तिहाई सदस्यों का प्रविधान किया गया। दो तिहाई सदस्यों का एक साथ दलबदल आसान नहीं था। कुछ राज्यों में धीरे-धीरे एक दो सदस्य किस्तों में आते गए और दलबदल को विलय माना जाता रहा।दलीय अनुशासन भी दलबदल का मुख्य तत्व बना। सदस्य द्वारा विधानमंडल दल के प्राधिकारी के जारी निदेर्शों को न मानना अथवा प्राधिकारी के निदेर्शानुसार मतदान न करना या मतदान से दूर रहना भी दलबदल कानून के अधीन दंडनीय है। व्यक्ति या समूह द्वारा जानबूझकर दल त्याग भी संभव है। कई बार दल अपनी विचारधारा बदलते हैं। कुछ सदस्यों को यह असहनीय लगता है।वे सदन में अपने दल के विरुद्ध बोलते हैं। विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार भी दलीय अनुशासन में नहीं मिलता। जबकि अनु. 105 एवं अनु. 194 में सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता है। कई बार सदस्य को अपने अथवा दल के विचार बदल जाने के कारण भी कठिनाई आती है। तब दलीय अनुशासन तानाशाही हो जाता है।राजनीतिक स्थिरता के लिए दलबदल पर रोक भी जरूरी है, लेकिन इसे सालाना बजट या अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण अवसरों तक सीमित रखना होगा। असहमत होने का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा है। इस कानून ने राष्ट्रीय विमर्श आधारित लोकतंत्र की जगह दलों और सदस्य संख्याओं का लोकतंत्र बना दिया है।यह भी याद रहे कि असहमति और दलबदल एक नहीं है। असहमति मौलिक अधिकार है और दलबदल अनैतिक। संविधान ने दलबदल के मामलों की सुनवाई का अधिकार सदनों के अध्यक्षों/सभापतियों को दिया है। उन पर आरोप है कि वह उचित कर्तव्य पालन नहीं करते। चुनाव आयोग का सुझाव है कि इस पर विचार के लिए स्वतंत्र आयोग बनाना चाहिए।सुझाव यह भी है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना था कि यह अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरकारों को बचाने के लिए लागू होता है।भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका महत्वपूर्ण है। उसे संविधायी और विधायी अधिकार भी हैं। इसलिए दसवीं अनुसूची के विचारण में अध्यक्षों/सभापतियों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। दसवीं अनुसूची में भी अध्यक्ष/सभापति को ही स्वेच्छया दल त्याग का अधिकार है। किसी अन्य सदस्य को यह अधिकार नहीं है। ये दल त्याग सकते हैं, बाकी सदस्य नहीं। आवश्यकता इसकी है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना समुचित कर्तव्य पालन करें, किसी प्रभाव या दबाव में नहीं।कर्तव्य निर्वहन में ढिलाई के कारण ही विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों पर टिप्पणियां हो रही हैं और राज्यपालों पर भी। केरल के राज्यपाल आर्लेकर ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कहा कि कोर्ट को यह मामला बड़ी बेंच को सौंपना चाहिए था। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक संस्था हैं। सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च आसन को टिप्पणी के दायरे में न लेता तो अच्छा होता। इस निर्णय पर और भी सवाल उठे हैं। उचित यही है कि संस्थाएं अपना कर्तव्य पालन करें।

खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

विजय गर्ग

हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद की ओर से एक निजी कंपनी के साथ मिल कर तैयार की गई रपट में बताया गया है कि देश के कृषि कार्यबल में 64.4 फीसद महिलाएं हैं, लेकिन सिर्फ छह से दस फीसद महिलाएं कृषि और इससे संबंधित शीर्ष कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं। इस रपट ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और शीर्ष पदों पर उनकी कम उपस्थिति के बीच गहरी खाई को उजागर किया है। रपट के मुताबिक कृषि व्यवसाय का भविष्य महिलाओं को शिक्षा, को शिक्षा, कार्यस्थलों समावेश बढ़ा कर और नेतृत्व विकास के माध्यम है। रपट में यह सशक्त बनाने में निहित आया है कि कृषि शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं का 30-40 फीसद नामांकन ही होता है, लेकिन इनमें से बहुत कम औपचारिक कृषि क्षेत्र में रोजगार पाती हैं।इसलिए कृषि में महिलाओं के करने की जरूरत है। उनकी सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने की समान भागीदारी समर्थन करने से ही कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाया जा सकता है। तभी इसका लाभ समाज सभी सदस्यों को मिल सकेगा। रपट के हवाले से विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी । होगी। मगर उच्च शैक्षणिक स्तर केबावजूद मजबूत औपचारिक रोजगार में उनकी संख्या नगण्य है। इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। रपट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां सुझाई हैं। इनमें महिलाओं को संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना और समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देकर उनको नेतृत्व के लिए प्रेरित करना शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कृषि परिदृश्य एक आश्चर्यजनक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। महिलाएं कृषि कार्यबल और शैक्षिक समूहों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी स्नातकों एक बड़ा हिस्सा औपचारिक रोजगार संरचनाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। हमें इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए समाधान के रास्ते खोजने होंगे।

असल में, कृषि में स्त्रियों की भागीदारी बहुआयामी प्रक्रिया है, जो कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। कृषि में महिलाओं की पूर्ण और बराबर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के कड़ों के अनुसार, भारत में कृषि श्रम बल में महिलाएं महत्त्वपूर्ण अनुपात में हैं। वर्ष 2010-11 की अवधि में लगभग 43 फीसद किसान और 52 फीसद कृषि मजदूर महिलाएं थीं। मगर समय साथ कृषि श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। वर्ष 2002--03 में महिला कृषकों का अनुपात 37 फीसद से बढ़ कर वर्ष 2010-11 में 43 फीसद हो गया। इसी अवधि में महिला कृषि मजदूरों 1143 का अनुपात 48 फीसद से बढ़ कर 52 फीसद हो गया।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा कृषि में अहम भूमिका निभाई है, चाहे वे किसान हों या मजदूर। हालांकि उनके योगदान को अक्सर अनदेखा किया और कम करके आंका जाता है। उन्हें इस क्षेत्र में समान भागीदारी और निर्णय लेने मेंकई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारकों में से एक, इस क्षेत्र में पुरुष श्रम शक्ति में गिरावट है। यह गिरावट कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें कृषि का मशीनीकरण, गैर-कृषि रोजगार में बदलाव और बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पुरुषों का शहरी क्षेत्रों में पलायन शामिल है। नतीजतन, महिलाओं ने कृषि में अधिक से अधिक जिम्मेदारियां और भूमिकाएं निभानी शुरू की हैं।महिलाओं के बढ़ते योगदान को अब कम करके आंका नहीं जा सकता। उनको यह मान्यता विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और सरकारी पहलों संभव हुई है। खेती में स्त्रियों की भागीदारी सकारात्मक रूप से बढ़ी है। हालांकि उन्हें अब भी कृषि में समान भागीदारी के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि में भूमि और अन्य संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच अक्सर पुरुषों की तुलना में सीमित होती है। वर्ष 2010- 11 की अवधि में भारत 1 में केवल 13 फीसद महिला कृषकों के पास खेती की जमीन थी, जबकि 37 फीसद पुरुष कृषकों के कपास खेती की जमीन थी। यह असमानता अन्य संकेतकों में भी। दिखाई देती है, जहां महिलाओं की विस्तार सेवाओं और विपणन तक पुरुषों की तुलना में कम पहुंच है।

इस क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियों में भेदभाव और रूढ़िवादिता भी है, जो इस क्षेत्र में संसाधनों, ज्ञान और अवसरों तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करती है। इनका समाधान करने और खेती में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक है, जो जो इस क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं।इसमें ऐसी पहलें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य संसाधनों, ज्ञान और व तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करते हुए लोगों की पुरानी सोच को बदलना है। इसके लिए नागरिक समाज भी कृषि क्षेत्र की महिलाओं को सामूहिक रूप से संगठित करने, उन्हें उनके सभी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, विस्तार सेवाओं उनकी पहुंच को सक्षम तक 1 और उन्हें स्थायी आजीविका ₹बनाने प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए महिलाओं को भूमि और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करना होगा, जिसमें ऋण, विस्तार सेवाएं और भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। ।कृषि में महिलाओं के अवैतनिक और अनौपचारिक श्रम की मान्यता तथा मूल्य को बढ़ावो देना जरूरी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों सहित कृषि में महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को समर्थन देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना होगा।किसान संगठनों, सहकारी समितियों और अन्य स्थानीय संस्थाओं सहित सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। तकनीकी सहायता और वित्त पोषण के प्रावधान माध्यम से कृषि में महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों और उद्यमों के विकास का समर्थन करना होगा। महिलाओं के भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना होगा, ताकि उन्हें विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सके निस्संदेह कृषि में महिलाओं की भूमिका अहम है। वे खेती संबंधी कई काम करती हैं ।

आतंकी गतिविधि और भारत के विरोध के कारण पाकिस्तान भुखमरी और कर्ज में डूबा

संजीव ठाकुर

स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे और पीछे जाता चला गया।पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें आई सब ने भारत का खुलकर विरोध किया और चीन के साथ मिलकर भारत के विरोध में आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देकर भुखमरी के गर्त में देश को डूबो दिया है, पाकिस्तान अपने सालाना बजट का अधिकांश पैसा सेना और आतंकवादी गतिविधियों में लगाकर अपनी अवाम को बेसहारा, भूखा छोड़ दिया , आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और चीन के कर्ज में सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है। पिछले 5 सालों से पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। पाकिस्तान आवाम भुखमरी और कर्ज की बेतहाशा शिकार हो गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को आटा, दाल,चीनी,बिजली और पेट्रोल पहले से लगभग चार गुना महंगी दरों में लेना पड़ रहा है। शरीफ सरकार दोबारा आने के बाद पूरी तरह विफल हो गई, प्रधानमंत्री शरीफ की चीन यात्रा पूरी तरह विफल रही है अब शरीफ सरकार ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेने पर देशद्रोह की कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है। कई मीडिया एजेंसियों पर इस संदर्भ में भारत से संबंधित किसी भी जानकारी प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल भारत के विरोध के मुद्दे को छोड़कर चीन ने पाकिस्तान का आर्थिक हालातो को सुधारने में कोई मदद करने का आश्वासन नहीं दिया है।पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को आर्थिक मदद कर घटनाओं का अंजाम देने में लगा है। ऐसे में वैश्विक नशे में पाकिस्तान के मानचित्र का विनष्ट होना निश्चित माना जा रहा है।पाकिस्तान पहले से ही परेशान, कर्ज में डूबा हुआ और महंगाई, बेरोजगारी से बुरी तरह त्रस्त रहा है।ह्ल शहबाज शरीफ सरकार के पास शासन चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी नहीं है।ह्ल शरीफ के पास सरकार चलाने का पर्याप्त अनुभव भी नहीं है।ह्ल 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान सरकार में 19 प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है ।करेला ऊपर से नीम चढ़ा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना और शाहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर रखा है। रावलपिंडी में इमरान खान पर गोली दागने से क्रोधित समर्थकों ने कई जगह सेना पर आक्रमण कर मेजर जनरल, गृहमंत्री राणा और प्रधानमंत्री के निवास को घेरकर तोड़फोड़ की थी। 1947 से स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब सेना के विरुद्ध पाकिस्तानी आवाम खुलकर विद्रोह करने पर आमादा है। ऐसा लगता है कि वहां सरकार तथा सेना के विरुद्ध आम नागरिकों का विद्रोह हो जाएगा। पहली बार कमर जावेद की सेना आवाम से डरी दिखाई दे रही है, पाकिस्तान विद्रोह की ज्वालामुखी पर बैठा है कभी भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है। यह तथ्य सार्वजनिक है कि पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा शागिर्द देश है। अमेरिका ने इसी के फल स्वरुप पाकिस्तान को सबसे संदिग्ध एवं खतरनाक आतंकवादी देश घोषित कर दिया है। इस बात से तिलमिलाकर शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं वहां वह आपसी संबंधों को फिर से सुधारने तथा देश चलाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाने जाएंगे। पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब एवं पतली है। पाकिस्तान में रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे नहीं है और उस पर इमरान खान के समर्थक लगातार सड़कों पर मार्च कर रहे हैं ।

मुंबई में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने के 65% चांस, महाराष्ट्र में मॉनसून को लेकर आई गुड न्यूज

- मुंबई में मॉनसून में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना
- मौसम विभाग की रिपोर्ट में मॉनसून के पैटर्न पर जानकारी
- दिन के तापमान में गिरावट, लेकिन उमस में बढ़ोतरी हुई

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबई : इस बार मॉनसून में मुंबई, उपनगर और आसपास अच्छी बारिश के संकेत हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में सामान्य से अधिक बारिश होने की 65% संभावना का है। प्राथमिक पूर्वानुमान सही साबित हुआ, तो मॉनसून में यहां अच्छी बारिश होगी, जो मुंबईकरों के लिए राहत भरी खबर है।मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पानी की काफी खपत है, जो यहां की झीलों से पूरी होती है। झीलों में जमा बारिश का पानी मुंबई की साल भर प्यास बुझाता है।ऐसे में, अच्छी बारिश होती है, तो मुंबईकरों को पानी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।हर जगह महाराष्ट्र में पहुंचेगा मॉनसूनमौसम विभाग के प्राथमिक पूवार्नुमान के अनुसार इस बार मुंबई सहित महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर यह है कि लगभग सभी जगह मॉनसून की उपस्थिति होगी। कई जगह नॉर्मल, तो कई जगहों पर सामान्य से अधिक तो कई क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है।मुंबई में होगी खूब झमाझमक्षेत्रीय मौसम विभाग की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना 65% है। हालांकि, मौसम विभाग की एक और रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें मॉनसून के पैटर्न को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।

हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं!... सरकार के फैसले पर भड़के राज ठाकरे बोले-तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है

- बोले-मनसे इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, रोलबैक की मांग
- फडणवीस सरकार ने पांचवी तक की है हिंदी अनिवार्य

हिंदी को अनिवार्य करने पर भड़क मनसे चीफ राज ठाकरे

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबईः दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हिंदी को लेकर पिछले दिनों हुए विवाद के बाद अब महाराष्ट्र भी इसकी जद में आ गया है। महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है।ठाकरे ने एक बयान में कहा है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे ने इसमें लिखा है 'हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं! अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है।' ठाकरे ने आगे लिखा है अगर आप यह सब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सरकार जानबूझकर यह संघर्ष पैदा कर रही है। क्या यह सब आने वाले चुनावों में मराठी और गैर-मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है?

क्या बोले राज ठाकरे?

राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की ये कोशिशें महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की हैं, जो पूरी तरह गलत है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि एक राज्य भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं हैं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है, उसे सरकारी मामलों तक सीमित रखें, शिक्षा में न लाएं।

ठाकरे ने लिखा है कि भारतीय संविधान में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है और अब इस पर हमला किया जा रहा है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह कदम महाराष्ट्र की संस्कृति और भाषा को कमजोर करने का प्रयास है। महाराष्ट्र की एक पहचान है, और हम मराठी भाषा के सम्मान की रक्षा करेंगे। राज ठाकरे की यह नाराजगी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब फडणवीस सरकार के फैसले सफाई दे चुके हैं। इससे पहले राज ठाकरे की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई थी।

फास्ट ट्रैक

रविवार, 20 अप्रैल, 2025 को पश्चिम रेलवे पर दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

पश्चिम रेलवे का 18/19 अप्रैल, 2025 की मध्यरात्रि को वसई रोड और वैतरणा के बीच रात्रिकालीन ब्लॉक

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबई, रेलपथ, सिगनलिंग और ओवरहेड उपकरणों के रख-रखाव हेतु शुक्रवार/शनिवार की मध्यरात्रि अर्थात 18/19 अप्रैल, 2025 की मध्यरात्रि को वसई रोड और वैतरणा स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर तीन घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप फास्ट लाइन पर ब्लॉक 23.50 बजे से 02.50 बजे तक लिया जाएगा, जबकि डाउन फास्ट लाइन पर यह ब्लॉक 01.30 बजे से 04.30 बजे तक रहेगा। ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 19101 विरार-भरूच मेमू 10 मिनट की देरी से चलेगी और इसलिए अपने निर्धारित प्रस्थान 04:35 बजे के बजाय 04:45 बजे विरार से प्रस्थान करेगी।इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध है।इसलिए, इस रविवार, 20 अप्रैल, 2025 को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन का पहला लुक

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड मेट्रो लाइन 3 के मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) बना रही है। एमसएमआरसीएल के आधिकारिक हैंडल ने सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन का पहला लुक पोस्ट किया है।भक्त अब आराम से मुंबई मेट्रो में बैठकर सिद्धिविनायक स्टेशन उतर कर गणपति बाप्पा का दर्शन कर सकेंगे। यह सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक के बीच शुरू होने वाले मेट्रो रूट पर बना है।

तस्वीरों में स्टेशन काफी खूबसूरत नजर आ रहा है।सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और नामी मंदिरों में से एक है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में प्रसिद्ध भगवान गणेश मंदिर है। यहां का मेट्रो स्टेशन मंदिर के बिल्कुल बगल में सटकर बनाया गया है ताकि श्रद्धालु मेट्रो से उतरकर सीधे में मंदिर में प्रवेश कर सकें और उन्हें कोई परेशानी न हो।मुंबई के नवनिर्मित सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन की पहली झलक दी गई है। अधिकारियों ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, मुंबई के सबसे सम्मानित मंदिरों में से एक के बगल में स्थित मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्लभ नजर, जहां आस्था डिजाइन के साथ जुड़ती है। संकीर्ण क्षेत्रों और निरंतर भीड़ से गुजरते हुए, स्टेशन को अतिरिक्त ध्यान और टीम वर्क के साथ बनाया गया था। आज, यह हजारों लोगों को सुविधा, तेजी और विचार के साथ आशीर्वाद से जोड़ता है।

पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनों के समय में परिवर्तन

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबई, पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार से चलने वाली कुछ ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। इनका विवरण नीचे दिया गया हैः

1. ट्रेन संख्या 19255 सूरत-महुवा एक्सप्रेस- 20 अप्रैल, 2025 से प्रभावी

ट्रेन संख्या 19255 सूरत-महुवा एक्सप्रेस का समय परिवर्तित किया गया है। अब यह ट्रेन सूरत से 22:00 बजे के बजाय 21:30 बजे प्रस्थान करेगी और महुवा 10:05 बजे के बजाय 09:40 बजे पहुंचेगी।

2. ट्रेन संख्या 12903 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल - 20 अप्रैल, 2025 से प्रभावी

ट्रेन संख्या 12903 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल का समय परिवर्तित किया गया है। अब इस ट्रेन का वडोदरा स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 23:39/23:49 बजे के बजाय 23:34/23:44 बजे होगा।

3. ट्रेन संख्या 20949 अहमदाबाद-एकतानगर जन शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20949 अहमदाबाद-एकतानगर जन शताब्दी एक्सप्रेस का समय परिवर्तित किया गया है। अब इस ट्रेन वडोदरा स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 16.46/16.49 बजे के बजाय 16.43/16.46 बजे होगा। (यह ट्रेन अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निरस्त की गई है)

4. ट्रेन संख्या 19007 सूरत-भुसावल पैसेंजर - 20 अप्रैल, 2025 से प्रभावी

ट्रेन संख्या 19007 सूरत-भुसावल पैसेंजर का समय परिवर्तित किया गया है। अब यह ट्रेन सूरत से 17:10 बजे के बजाय 17.00 बजे प्रस्थान करेगी। (यह ट्रेन वर्तमान में अगले आदेश तक सूरत के बजाय उधना से प्रस्थान करती है)

5. ट्रेन संख्या 69169 सूरत-नंदुरबार मेमू - 20 अप्रैल, 2025 से प्रभावी

ट्रेन संख्या 69169 सूरत-नंदुरबार मेमू का समय परिवर्तित किया गया है। अब यह ट्रेन सूरत से 18.15 बजे के बजाय 18.10 बजे प्रस्थान करेगी। (यह ट्रेन वर्तमान में अगले आदेश तक सूरत के बजाय उधना से प्रस्थान करती है)

6. ट्रेन संख्या 22967 अहमदाबाद-प्रयागराज एक्सप्रेस - 24 अप्रैल, 2025 से प्रभावी

ट्रेन संख्या 22967 अहमदाबाद-प्रयागराज एक्सप्रेस का समय परिवर्तित किया गया है।

अब इस ट्रेन का नंदुरबार स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 22.45/22.50 बजे के बजाय 22.50/22.55 बजे होगा।

7. ट्रेन संख्या 20929 उधना-बनारस एक्सप्रेस - 25 अप्रैल, 2025 से प्रभावी

ट्रेन संख्या 20929 उधना-बनारस एक्सप्रेस का समय परिवर्तित किया गया है। अब इस ट्रेन का नंदुरबार स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 22.45/22.50 बजे के बजाय 22.50/22.55 बजे होगा।

विस्तृत जानकारी तथा मध्यवर्ती स्टेशनों के बीच ट्रेनों के ठहराव समय की जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

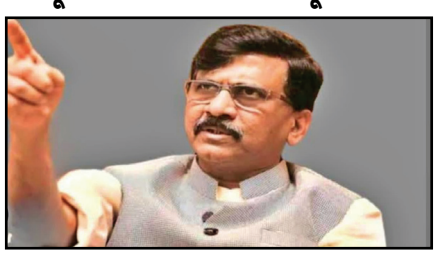

'आपके पेट में दर्द क्यों?' बाल ठाकरे के एआई भाषण पर भड़की बीजेपी को संजय राउत का जवाब

सजय राउत ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पर हमला किया और पूछा कि मालवण में शिवाजी की मूर्ति क्यों गिरी?

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबईः आज के दौर में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का बोलबाला है. वहीं, अब इसका असर राजनीति पर भी पड़ने लगा है. नासिक में शिवसेना (एआई) ने एआई के जरिए बालासाहेब की आवाज में भाषण दिया गया. बीजेपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ने इसकी आलोचना की है.इस संबंध में शिवसेना (एआई) सांसद संजय राउत ने कहा, फर्जी लोगों को हमारी आलोचना नहीं करनी चाहिए. अमित शाह ने बालासाहेब के नाम पर फर्जी शिवसेना बनाई है. इस दौरान उन्होंने मंत्री शंभुराज देसाई पर भी निशाना साधा.

'देशद्रोहियों के लिए कोई माफी नहीं'

मंत्री शंभुराज देसाई के बालासाहेब की आवाज की आलोचना करने पर संजय राउत ने कहा कि क्या कांग्रेस से मेंढक की तरह आए शंभूराज देसाई हमें विचारधारा सिखाएंगे? आनंद दिघे, क्या शंभूराज देसाई अब हमें बालासाहेब ठाकरे के बारे में सिखाएंगे? देशद्रोहियों के लिए कोई माफी नहीं है. वे सभी गुमराह हैं.

शिवसेना सांसद ने कहा कि अमित शाह ने शिंदे और उनकी पार्टी को चेतावनी दी है या तो फडणवीस की सेवा करें, या सरकार से बाहर हो जाएं. यह सरकार आपके बिना चलेगी. इसलिए हम भाजपा के बर्तन धोएंगे. हम सेवा करेंगे,

लेकिन हम बाहर नहीं निकल सकते, वे ऐसे ही हैं. इसलिए उन्हें हमें नहीं सिखाना चाहिए.

बालासाहेब की आवाज के साथ पहली बार प्रयोग नहीं

आपने दो धर्मवीर फि ल्में बनाईं और धर्मवीर आनंद दिघे के नाम पर फर्जी विचार फैलाए, क्या यह ठीक है? सांसद संजय राउत आपके पेट में दर्द का कारण क्या है? दूसरी तरफ, अमित शाह ने शिंदे की पार्टी बनाई है. इसलिए उन्हें लगता होगा कि यह फर्जी आवाज है! हमने बालासाहेब की आवाज के साथ पहली बार प्रयोग नहीं किया. इससे पहले बालासाहेब की आवाज का इस्तेमाल मुंबई कैंप में भी अक के जरिए किया गया था.

बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की

उन्होंने कहा कि बालासाहेब के विचारों पर उनका कोई अधिकार नहीं है. शिंदे ने धर्मवीर फिल्म बनाई. लेकिन उन्होंने उनके नाम पर सब कुछ फर्जी बनाया. हम आपसे ज्यादा आनंद दिघे के करीब थे.

टिकट दलालों पर रेलवे सुरक्षा बल ने की कार्रवाई

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

जबलपुर । भारतीय रेलवे में अवैध टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु पश्चिम मध्य रेल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन उपलब्ध के तहत माह जनवरी 2025 से 15 अप्रैल 2025 के दौरान अवैध टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत 13 प्रकरण दर्ज कर 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करते हुए 16 लाख 8 हजार 371 रुपए की रेल टिकट जब्त की गई। रेलवे एक्ट 143 के तहत, किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा रेलवे टिकटों का अवैध तरीके से व्यापार करना, अधिक दाम पर बेचना या अन्य किसी तरीके से टिकटों की कालाबाजारी करना कानूनी अपराध है। इस एक्ट के तहत जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।

मुख्य बिंदुः-

1) कानूनी कार्रवाईः दोषियों के खिलाफ जुर्माना और दण्ड का प्रावधान।

2) अवैध गतिविधियों पर रोकः टिकटों की कालाबाजारी और अवैध बुकिंग पर नियंत्रण।

3) रेलवे प्रशासन की पहलः यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

रेलवे विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट केवल आधिकारिक रेलवे काउंटरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से ही बुक करें। अवैध बुकिंग से बचने के लिए कृपया हमेशा अधिकृत स्त्रोतों से ही टिकट प्राप्त करें। रेलवे सुरक्षा बल की यह कार्रवाई यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सुनिश्चितता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6 साल के लंबे इंतजार के बाद अमरावती एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू, मुंबई का सफर बस 2 घंटे में

मुंबईः छह साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अमरावती एयरपोर्ट से विमान उड़ना शुरू हो गया। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने मंत्रियों के साथ विमान से पर लैंड किया। अमरावती एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से सलामी देकर विमान का स्वागत किया गया। अमरावती और मुंबई के बीच सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को विमान सेवा शुरू रहेगी।कब शुरू हुआ था अमरावती एयरपोर्ट का काम?विदर्भ के लिए महत्वपूर्ण माने जाने अमरावती एयरपोर्ट का काम सन 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। कई महीनों तक काम बंद रहा, लेकिन अब काम पूरा हो गया। मुंबई से अमरावती की दूरी रेल यात्रा से करने पर 12 घंटे लगते हैं लेकिन हवाई सेवा शुरू होने से यह सफर मात्र 2 घंटे में पूरा हो जाएगा।क्या बोले सीएम फडणवीस?अमरावती एयरपोर्ट पर विमान से पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि अमरावती ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ के विकास में यह नया एयरपोर्ट बहुत उपयोगी साबित होगा। यहां पर एक पायलट प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया जा रहा है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा स्कूल होगा। हर साल अमरावती से 180 पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा और लगभग 34 विमान खड़े किए जाएंगे। ये विमान प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

पश्चिम रेलवे उधना और बरौनी के बीच चलाएगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबई, पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उधना और बरौनी के बीच विशेष किराये पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09037/09038 उधना-बरौनी साप्ताहिक विशेष ट्रेन [22 फेरे]

ट्रेन संख्या 09037 उधना-बरौनी स्पेशल प्रत्येक रविवार को उधना से 05.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 15.00 बजे बरौनी जं. पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 अप्रैल से 29 जून, 2025 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09038 बरौनी-उधना स्पेशल प्रत्येक सोमवार को बरौनी से 18.30 बजे प्रस्थान करेगी और बुधवार को 04.00 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अप्रैल से 30 जून 2025 तक चलेगी।यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, बारडोली, नंदुरबार, अमलनेर, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर और मोकामा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09037 की बुकिंग 18 अप्रैल, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मध्य रेल

माटुंगा कारखाना में ईएमयु कोचों के पंखों और टयुबलाइटों की स्ट्रिपिंग, सफाई, पेंटिंग और फिटिंग

उप. मुख्य विद्युत अभियंता (ईएमयु), तीसरी मंजिल, नवीन प्रशासकीय भवन, सवारी कारखाना, मध्य रेल्वे, माटुंगा, मुंबई - 400019, " माटुंगा कारखाना में ईएमयु कोचों के पंखों और टयुबलाइटों की स्ट्रिपिंग, सफाई, पेंटिंग और फिटिंग। **मात्रा:** 1064 कोच" कार्य के लिये इ-निविदा आमंत्रित करते है। **अनुमानित लागत:** रु. 1,33,02,175.68/-. **ईएमडी:** रु. 2,16,500/-. **निविदा प्रपत्र शुल्क:** शुन्य। **समापन अवधी:** 24 माह। **निविदा जमा करने की समाप्ति दिनांक एवं समय:** 13.05.2025, 15:00 बजे। निविदा केवल इ टेण्डरिंग फॉरमॅट मे वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। निविदा पुस्तिका वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निविदा संख्या - EMUMTNETL 10640410-24RT. **AK-41**

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

वरिष्ठ सं.इ.एन. (मध्य) एमएमसीटी, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008 आमंत्रित करता है, सं.:1. **निविदा सूचना सं.** बीसीटी/25-26/6, दिनांकः 07.04.2025. **कार्य और स्थानः** (i) जोरवासन – सूरत खंडः विरार सूरत – टीआरआर (पी) – 3.416 टीकेएम और टीएसआर (पी) –9.882 टीकेएम के संबंध में ट्रैक का रखरखाव। (ii) जोरवासन – उकाई खंडः वरिष्ठ सं.इ.एन./मध्य खंड के तहत विभिन्न स्थानों पर मानसून के पानी को बाहर निकालने के लिए स्लज डीजल पंप प्रदान करना। **कार्य की अनुमानित लागतः** 2,56,17,621.12। **ईएमडीः** 2,78,100/–। सं.:2। निविदा सूचना संख्या BCT/25–26/7, दिनांकः 07.04.2025। **कार्य और स्थानः** विरार – उकाई सोंगहाद खंडः विरार से उकाई–सोंगहाद खंड के बीच ट्रैक आधारित रेल गेज फेस लुब्रिकेटर (इलेक्ट्रॉनिक प्रकार और 1 किमी तक कैरी डाउन प्रभाव) की आपूर्ति, स्थापना कमीशन और संचालन (5 वर्ष)। **कार्य की अनुमानित लागतः** 1,92,16,458/–। ईएमडीः ' 2,46, 100/–। दोनों निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि और समयः 13.05.2025, 15:00 बजे तक। दोनों निविदाएं खोलने की **अंतिम तिथि और समयः** 13.05.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0052

facebook.com/WesternRly

पश्चिमी रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना संख्या एस/21/2025 दिनांक 15.04.2025

क्रमांक	वस्तु का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	T.O.D.
184	ड्रग एल्यूटिंग कोरोनरी स्टेंट सिस्टम	200 नग	12-मई-25
185	हाई टेन्साइल एएआर एच टाइप टाइट लॉक कपलर की आपूर्ति।	20 नग	19-मई-25
186	एमवी बोर्ड मेसर्स फाइवले मेक को ओईएम द्वारा प्रदान की गई कंडीशन बेस्ड आइटम सूची का पार्ट नंबर 1/600006।	42 नग	26-मई-25
187	6.2 मिमी मोटी कम्पोजिट ग्रूव्ड रबर सोल प्लेट	3500000संख्या	28-मई-25

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के संबंध में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in देखें। 0051

facebook.com/WesternRly • X.com/WesternRly

पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग

(भंडार आपूर्ति हेतु 'ई' निविदा सूचना, संख्या EPS/68/2025)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, ई–खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते हैं। कोई भी हस्तलिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए "https://ireps.gov.in" पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की सकती है।

क्रं.	टेंडर नं.	संक्षिप्त वर्णन	निविदा संख्या
1	38241728B	ब्रेक बीम प्राथमिक	661संख्या
2	30241055	आरडीएसओ से एंकर लिंक के लिए साइलेंट ब्लॉक की खरीद	11420संख्या
3	38242200	एडाप्टर ए.ए.आर. स्टैंडर्ड वाइड जॉ.	6531संख्या
4	80251056	WAG-9/WAP7 लोको एक्सल बॉक्स बेयरिंग के लिए शेल गैडस S5 V42P ग्रीस	10300किग्रा.
5	80251017	हाइड्रोलिक तेल एचएलपी – 68 एन आरडीएसओ अतिरिक्त आवश्यकता के साथ।	76630 एलटीआर
6	38251918	हैंड ब्रेक व्यवस्था के लिए केबल असेंबली	2068संख्या
7	38241347	वितरक वाल्व पूर्ण	412संख्या

उपरोक्त निविदाओं की नियत तिथि क्रमांक 1 और 2 – 12.05.2025, क्रमांक 3 – 14.05.2025, क्रमांक 4 – 15.05.2025, क्रमांक 5 – 19.05.2025, क्रमांक 6 – 22.05.2025 और क्रमांक 7 – 28.05.2025 है। 50 लाख रूपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए, इच्छुक फर्मों को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है।

(हस्ता.)
कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पमरे, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम रेलवे

टीआरडी कार्य

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (उप), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल ई-निविदा संख्याः WR-MMCTOESUB(ESOT)/09/2025 आमंत्रित करता है। **दिनांकः** 15.04.2025। कार्य का नामः लोअर परेल - ईएमयू कार्यशाला में दोहरी प्रविष्टि/निकास के संबंध में टीआरडी कार्य। **कार्य की अनुमानित लागतः** 53,90,730/-। **बोली सुरक्षाः** 1,07,800/-। **जमा करने की तिथि और समयः** 13.05.2025, 15:00 बजे तक। **खुलने की तिथि और समयः** 13.05.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं 0053

facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

ई-निविदा सुचना

मुख्य परियोजना प्रबंधक (गति शक्ति, सोलापुर, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी और से दिनांक को बजे तक निम्नलिखित कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित करते है। **ई-निविदा सुचना क्र. 01-2025-GSU-Civil. दिनांक:15.04.2025 कार्य का नाम: (A)** अक्कलकोट रोड स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन के लिए एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) तक रैम्प की सुविधा प्रदान करना (सोलापुर मंडल के अंतर्गत)। **(B)** अक्कलकोट रोड स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत लिफ्ट की सुविधा प्रदान करना (सोलापुर मंडल के अंतर्गत)। **(C)** पार्सल और माल गोदाम से संबंधित सुविधाओं का निम्नलिखित स्थानों पर प्रावधान (i) **सोलापुरः** सीजीएस कार्यालय एवं पार्सल कार्यालय का प्रावधान। (ii) **कलबुर्गीः** पार्सत कार्यालय का प्रावधान। (iii) **कुर्दुवाडीः** हमाल कक्ष एवं सीजीएस कार्यालय का प्रावधान। (iv) **वाड़ीः** पार्सत कार्यालय एवं स्टोर रूम का प्रावधान। (v) पंढरपुरः हमाल कक्ष का प्रावधान। **(D) वाड़ी-** वाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1/2 और 3/4 की सतह को पुनः निर्मित करना तथा अन्य सुधारात्मक कार्य करना। **अनुमानित लागत:** रु.21,31,91,771,00. **बयाना रक्कम:** रु. 12,16,000.00. **समापन की अवधी:** 12 (बारह) महीने। **अनुरक्षण की अवधी:** 6 महीने या एक मानसून जो बाद में होता है। **वेबसाइट ई-निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तारीख और समय: 09.05.2025 up to 15.00** hrs. **वेबसाइट ई-निविदा खोलने की तारीख और समय: 09.05.2025 after 15.30** hrs. **वेबसाइट विवरण: www.ireps.gov.in** निविदाकारों से निवेदन हैं की कोई बदलाव शुद्धिपत्र (यदि हो) के लिये **Website: www.ireps.gov.in** पर टेंडर बंद होने की तारीख तक समय समय पर भेंट दे।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक (गति शक्ति)
Akar/Sur- 40 मध्य रेल, सोलापूर

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

कांग्रेस ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

ठाणे , मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और नफरत व बदले की भावना से 'नेशनल हेराल्ड' अखबार की संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कदम उठा रही है। सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग कर आरोप में आरोपपत्र दायर करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्से का माहौल है और देशभर में ईडी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके तहत महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल के निर्देशानुसार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कोंकण सह प्रभारी यू.बी. वेंकटेश के नेतृत्व में ठाणे के कोर्ट नाका स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं कोंकण सह-प्रभारी यू बी वेंकटेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ है। यह एक राजनीति से प्रेरित कार्रवाई थी और गांधी परिवार को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा था। हम इस लड़ाई का सामना सत्य और न्याय की ताकत से करेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ठाणे जिला कलेक्टर अशोक शिंगारे से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा इस विरोध प्रदर्शन में ठाणे कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, पूर्व सांसद कुमार केतकर, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्याताई सव्वालखे, प्रदेश पदाधिकारी चंद्रकांत पाटिल, संतोष केणे, ठाणे ग्रामीण अध्यक्ष दयानंद चोरघे, कल्याण शहर अध्यक्ष सचिन पोटे, उल्हासनगर अध्यक्ष रोहित साल्वे, भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन, ठाणे कांग्रेस प्रवक्ता राहुल पिंगले सहित जिले भर के विभिन्न फ्रंटल और सेल नेता सहित बड़ी संख्या में सभी स्तर के कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।

शिवसेना ने प्रतीक सुनील शर्मा को सोशल मीडिया उप राज्यप्रमुख पद पर नियुक्त किया

सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी का प्रचार प्रसार और पार्टी को जनता से सीधे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अंबरनाथ.गुरुवार 17 अप्रैल को शिवसेना ने अंबरनाथ निवासी प्रतीक सुनील शर्मा को आगामी एक वर्ष के लिए पार्टी के सोशल मीडिया उप राज्यप्रमुख पद पर नियुक्त किया है। प्रतीक सुनील शर्मा को उक्त पद का नियुक्ति पत्र गुरुवार को शिवसेना सचिव संजय पुष्पलता भाऊराव मोरे के लेटर पेड़ से शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय से निकाला गया है। प्रतीक शर्मा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कल्याण लोकसभा के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के सोशल मीडिया प्रभारी का कार्य देखते रहे हैं। सांसद डॉ.श्रीकांत शिंदे ने इस पद पर नियुक्त होने पर प्रतीक सुनील शर्मा को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया उपराज्य प्रमुख पद पर प्रतीक सुनील शर्मा आगामी एक वर्ष के लिए बालासाहब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे आदि के विचारों सिद्धांतों का पार्टी हित में प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी की नीतियों,सिद्धांतों,संगठन का सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी संगठन के लिए सोशल मीडिया पर रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करेंगे और पार्टी हित में सोशल मीडिया पर पोस्ट और सामग्री का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पार्टी की छवि और पार्टी के संदेशों को सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए जनता के मुद्दों को समझेंगे और पार्टी की नीतियों और कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम जनता तक पहुंचाएंगे। अंबरनाथ में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रतीक सुनील शर्मा के शुभचिंतकों में खुशी की लहर है और उनको बधाई संदेश देने वालों का तांता लगा है।

फास्ट ट्रैक

पुराने विवाद में दोस्तों ने दुकानदार को मारी गोली

हालत गंभीर, लखनऊ रेफर; आरोपी फरार

शाहजहांपुर, थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक दुकानदार को उसके पुराने दोस्तों ने गोली मार दी। घटना अंटा चौराहे के पास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के निकट हुई। नितिन नाम का युवक यहां परचून की दुकान चलाता है। रात करीब 11 बजे उसके कुछ पुराने दोस्त दुकान पर आए। नितिन का इन दोस्तों से पहले से विवाद चल रहा था। आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की। लोगों ने बीच-बचाव कराया। कुछ देर बाद आरोपी फिर लौटे। उन्होंने नितिन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक आरोपी ने नितिन के पेट में गोली मार दी। नितिन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल नितिन को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

कौशल्या, महावीर जैन अस्पताल गरीब मरीजों पर होने वाले खर्च रिपोर्ट दें : नारायण पवार

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

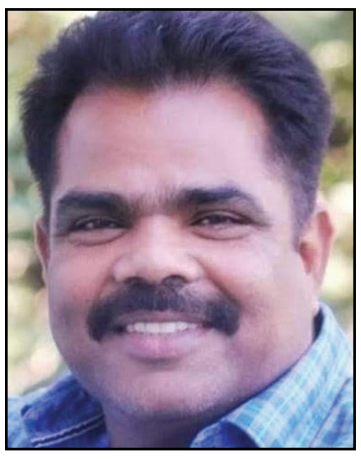

ठाणे , पूर्व भाजपा गटनेता नारायण पवार ने मनपा आयुक्त सौरभ राव को पत्र लिखकर मांग की है कि शहर के कौशल्या अस्पताल और श्री महावीर जैन अस्पताल द्वारा पिछले पांच वर्षों में गरीब मरीजों के लिए उपयोग की गई राशि, साथ ही शहर के धर्मार्थ अस्पतालों में जमा राशि पर रोक लगाई जाए और गरीब व कमजोर वर्ग के लिए प्रतिदिन उपलब्ध 20 प्रतिशत आरक्षित सीटों का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। नारायण पवार ने आरोप लगाया है कि शहर के चैरिटेबल अस्पतालों में गरीब मरीजों से भी अधिक बिल वसूला जा रहा है और उन्हें जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में जमा राशि का भुगतान न किए जाने के कारण एक महिला की मौत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे उपचार देने से इनकार कर दिया गया। नारायण पवार ने गरीब मरीजों के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च न किए जाने के मद्देनजर ठाणे शहर के तीन अस्पतालों की ओर भी मनपा प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। पांचपाखड़ी में कौशल्या मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट अस्पताल और लुइसवाड़ी में श्री महावीर जैन अस्पताल तथा श्री प्रताप जे. आशर कार्डियक सेंटर को मनपा ने भूमि उपलब्ध कराई है। तो ठाणे में पोखरण रोड नं.2 में बेथनी अस्पताल एक धर्मार्थ अस्पताल के रूप में कार्य करता है।कौशल्या और बेथनी अस्पतालों में गरीबों और कमजोर लोगों के लिए आरक्षित सीटों का विवरण आम नागरिक की समझ में नहीं आता है। इसलिए, उपलब्ध स्थान और इस स्थान पर इलाज करा रहे मरीजों के नाम अस्पताल की वेबसाइट पर घोषित किए जाने चाहिए। श्री महावीर जैन अस्पताल में 10 प्रतिशत बेड गरीब मरीजों के लिए निशुल्क उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए अन्यथा पूर्व नगरसेवक नारायण पवार ने मांग की है कि मनपा द्वारा इस ट्रस्ट को दिया गया भवन वापस लिया जाए।ठाणे शहर के सभी निजी अस्पतालों को सबसे पहले मरीजों के रिश्तेदारों को इलाज के खर्च की तय राशि के बारे में सूचित करना चाहिए। मनपा प्रशासन को मनपा क्षेत्र में निजी अस्पतालों का निरीक्षण, पंजीकरण या नवीनीकरण करने का अधिकार है। नारायण पवार ने पत्र में कहा है कि इस संबंध में शहर के निजी अस्पतालों के प्रबंधन को नियमानुसार उचित निर्देश दिए जाने चाहिए।

बाबा बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज के दर्शन अब भिवंडी में भी हो सकेंगे

भिवंडी में बने बागेश्वर धाम मंदिर के लिए अंबरनाथ,उल्हासनगर व कल्याण से बस सेवा शुरू करने की मांग।

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अंबरनाथ. मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विख्यात बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज का मंदिर अब महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में भी स्थापित हो गया हैं। भिवंडी तालुका के अंजुर दिवे में इंडियन कॉर्पोरेशन माईल स्टोन,दिवे अंजुर पेट्रोल पंप के सामने, नासिक हाइवे भिवंडी में भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अप्रैल को आयोजित किया गया था। इस मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मंत्रोच्चार के साथ की है। श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हनुमंत यज्ञ की पूर्णाहूति भी हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बद्रीनाथ वाले महाराज, मुख्य आयोजक रुद्र प्रताप त्रिपाठी सपरिवार मौजूद थे। बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त और अनुयाई उल्हासनगर, अंबरनाथ व कल्याण में लाखों की संख्या में हैं। यह मंदिर मुख्य राजमार्ग से भी 3 किमी अंदर है। बागेश्वर धाम के भक्तों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मंदिर तक के लिए बस सेवा शुरू की जाए। मंदिर समिति से भी अनुरोध किया है कि मंदिर परिसर में भक्तों के लिए भंडारा, जलपान और मंदिर में शेड की व्यवस्था की जाए ताकि दूर दूर से आने भक्तों को सुविधा मिल सके।

खेत से लापता हुआ युवक

शाहजहांपुर में 3 दिन से कोई सुराग नहीं, परिजनों ने थाने में दी शिकायत

शाहजहांपुर , कलान थाना क्षेत्र में एक मंदबुद्धि युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। गुन्दौरा दाउदपुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सतीश 15 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से लापता हैं। सतीश के पिता सांदर सिंह यादव ने बताया कि उनका बेटा खेत में गेहूं की फसल इकट्ठा करने गया था। वहां से वह वापस नहीं लौटा। सतीश अविवाहित है और मंदबुद्धि की स्थिति में है। परिवार ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सांदर सिंह ने थाने में जाकर गुमशुदगी की तहरीर दी है। कलान थाना पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी है।

पिकअप ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर

चालक समेत दो लोग गंभीर घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर

शाहजहांपुर, जलालाबाद में गुरुवार दोपहर 2 बजे सड़क हादसा हुआ। कलेक्टर गंज के पास सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा को पीछे से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक महेश पाल और सवारी रामकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। महेश पाल नगरिया भूड का रहने वाला है। वह रामकुमार के निमार्णाधीन मकान के लिए जलालाबाद से लकड़ी का सामान लेकर गांव की ओर जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा पलट गया। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण दोनों को मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया।

वर्षा जल संचय की बैठक में अधिशासी अभियंता गैरहाजिर

शाहजहांपुर डीएम ने जताई नाराजगी, निलंबन के लिए पत्र लिखने के दिए निर्देश

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वर्षा जल संचय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजू मिश्रा की अनुपस्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। डीएम ने अधिशासी अभियंता के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखने के निर्देश दिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना पर चर्चा की गई। इस योजना के तहत सरकारी और अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता लघु सिंचाई को पहले से बने वर्षा जल संचय सिस्टम की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्तूरबा विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और वन स्टाफ सेंटर की इमारतों पर वर्षा जल संचय सिस्टम बनाया जाए। डीएम ने सिंचाई विभाग को यह कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

पशुशाला में लगी आग

3 मवेशियों की मौत, 4 घायल; 2 मोटरसाइकिल जलकर राख

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर, जलालाबाद तहसील के गांव नौसारा में गुरुवार को एक बड़ी घटना सामने आई। यहां दोपहर करीब 4 बजे एक पशुशाला में अचानक आग लग गई। आग की इस घटना में 3 मवेशियों की जलकर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मवेशी घायल हो गए। पशुशाला राजीव सिंह, चिरंजीव सिंह और अरविंद सिंह की है। तीनों महेंद्र सिंह गुर्जर के पुत्र हैं और ग्राम पंचायत लहसड़ी के निवासी हैं। आग में दो मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गईं। आसपास के ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही शाम 5 बजे नायब तहसीलदार अनुराग दुबे और लेखपाल अखिलेश वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि पशु चिकित्सक को बुलाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सरकार की ओर से पशु हानि का मुआवजा दिलाया जाएगा। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

एडीएम ने किसान बनकर पकड़ा अवैध गेहूं से भरा ट्रक

तिलहर में हवाई चप्पल और गमछे के साथ खुफिया छापेमारी, 300 कुंटल जब्त

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर , तिलहर तहसील में एडीएम वित्त अरविंद कुमार ने एक अनोखे अंदाज में अवैध गेहूं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने ग्रामीण का भेष धारण कर खुफिया अभियान चलाया। एडीएम कुमार लोअर और टी-शर्ट पहने, हवाई चप्पल में और गले में गमछा डाले प्राइवेट गाड़ी से कटरा पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार जय प्रकाश यादव और मंडी सचिव शिवेंद्र प्रताप सिंह को भी वहां बुलाया। यह कार्रवाई बुधवाना रोड खमरिया स्थित एक अवैध आढ़त की सूचना पर की गई। अधिकारियों की टीम जब खमरिया पहुंची तो आढ़त पर गेहूं कम दिखा। लेकिन पास के मैदान में खड़े एक ट्रक को देखते ही एडीएम तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने ट्रक पर चढ़कर चालक से गेहूं के कागजात मांगे। कागजात नहीं दिखा पाने पर ट्रक को जब्त कर लिया गया। तिलहर मंडी समिति क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में करीब 300 कुंटल अवैध गेहूं जब्त किया गया। ट्रक को तिलहर नवीन मंडी स्थल पर ले जाया गया। एडीएम की इस कार्रवाई से अवैध गेहूं भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय किसानों ने एडीएम की इस कार्रवाई की सराहना की है।

महिला समेत तीन अफीम तस्कर गिरफ्तार

शाहजहांपुर में लाखों की अफीम बरामद, झारखंड से तस्करी करने आए थे

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर, पुलिस ने अफीम तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने झारखंड की एक महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपये कीमत की अफीम बरामद हुई है। रामचंद्र मिशन थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। खननौत पुल के पास कुछ लोग अफीम की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। मौके से तीन आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में अवनीश कुमार थाना कटरा क्षेत्र का निवासी है। अन्य दो आरोपी मुन्नी देवी और गुलाब कपूर झारखंड के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे झारखंड से सस्ते दाम पर अफीम लाते हैं। शाहजहांपुर में इसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। पकड़े जाने के समय आरोपी अलग-अलग जगहों पर पहले से तय ग्राहकों को अफीम बेचने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

मीटर लगे होने पर भी दर्ज की एफआईआर

विजिलेंस एसपी ने लिए उपभोक्ताओं के बयान; डीएम कर चुके हैं पूरी टीम के निलंबन की संस्तुति

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर, बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर गंभीर लापरवाही लगने के बाद बुधवार को बिजली विभाग के एसपी अरविंद मिश्रा ने गांव पहुंचकर पीड़ित उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए। देर रात मीडिया से बात करते हुए जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की बात की है। बता दें कि मीटर लगे होने के बावजूद 11 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मिजार्पुर थाना क्षेत्र के बहरिया गांव में विजिलेंस टीम प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने अपनी टीम के साथ चेकिंग की थी।

स्थानीय विधायक हरिप्रकाश वर्मा और उपभोक्ताओं ने 10 मार्च को डीएम से इसकी शिकायत की। डीएम के आदेश पर एडीएम एफआर अरविंद कुमार ने जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद डीएम ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर पूरी विजिलेंस टीम को निलंबित करने की सिफारिश की।

मामला शासन तक पहुंचने पर बुधवार को विजिलेंस एसपी अरविंद कुमार मिश्रा और सीओ विजिलेंस बरेली मिनाक्षी शर्मा शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने बहरिया गांव में पीड़ित उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए। ग्राम प्रधान ने विजिलेंस टीम पर डरा-धमकाकर वसूली करने का आरोप लगाया है। एसपी विजिलेंस ने कहा कि सीओ के नेतृत्व में जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव

अस्पताल कर्मी पर अपहरण की धमकी का आरोप, युवती ने बजरंगदल से मांगी मदद

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर , पुवायां में एक निजी अस्पताल में कार्यरत युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि पकड़िया हकीम गांव का तौहीद खान उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। युवती ने बताया कि तौहीद ने धोखे से उसका मोबाइल नंबर हासिल किया। वह अलग-अलग नंबरों से फोन कर उसे परेशान कर रहा है। तौहीद धमकी दे रहा है कि अगर वह निकाह नहीं करेगी तो उसका और उसके परिवार का अपहरण कर लेगा। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब युवती के परिवार ने तौहीद की पत्नी साहिबा से संपर्क किया। साहिबा ने कहा कि इस्लाम में तीन शादियां जायज हैं और युवती को आर्थिक लाभ व सुख-सुविधाएं देने का वादा किया। युवती ने 10 अप्रैल को पुलिस में शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने अनुचित सवाल पूछे और बिना कार्रवाई के उसे भगा दिया।

भारत संवाद परिवार

1-संरक्षक-भारत संवाद
डॉ राम किशोर शर्मा
पूर्व विभागाध्यक्ष इलाहाबाद विश्व विद्यालय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित,
2-संरक्षक-भारत संवाद
आचार्य पं0 पृथ्वीनाथ पाण्डेय
भाषाविज्ञानी एंव मीडियाध्ययन विशेषज्ञ
3-संरक्षक-भारत संवाद
गजानन महतपुरकर
(सुपरिचित कवि, लेखक, गीतकार, मंच संचालक, स्वतंत्र पत्रकार एवं सदस्य, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी तथा पश्चिम रेलवे, चर्चगेट के वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी पद से सेवानिवृत्त)
4-कला एवं मनोरंजन संपादक
(भारत संवाद)
जगन्नाथ तिवारी
5-उपसंपादक (भारत संवाद)
माता प्रसाद शर्मा
6-प्रभारी प्रयागराज संस्करण
(भारत संवाद)
आशीष कुमार शर्मा

सस्ता कर्ज देकर रूसी हथियारों का बाजार हथिया रहा भारत

ब्राजील-अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे डिप्लोमैट; रूस-यूक्रेन जंग का फायदा

एजेंसी

नई दिल्ली, भारत हथियार खरीदने वाले देशों को सस्ते और लंबे समय तक के कर्ज देने की पेशकश कर रहा है। टारगेट वे देश हैं, जो अब तक रूस से हथियार खरीदते रहे हैं। रूस के यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से ये देश अब नए विकल्प तलाश रहे हैं। भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह दावा रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी किया गया है। भारत, यूक्रेन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में सरकार हथियारों के निर्यात पर भी जोर दे रही है। इसके लिए भारत एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक के माध्यम से हथियार खरीदने के लिए कर्ज मुहैया करा रहा है। रॉयटर्स ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सरकार ईएक्सआईएम बैंक की मदद से हथियार खरीदने वाले देशों को कम ब्याज दरों पर और लंबे समय के लिए लोन देने के प्लान पर काम कर रही है। इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जो राजनीतिक अस्थिरता या कम क्रेडिट रेटिंग की वजह से महंगे कर्ज नहीं उठा पाते। भारत ने इसके लिए ब्राजील-

अर्जेंटीना समेत 20 देशों में अपने डिप्लोमैट भेजे हैं। भारत ने ईएक्सआईएम बैंक के जरिए लोन बांटने का फैसला किया है। दरअसल, भारत के ज्यादातर बैंक हथियारों की बिक्री के लिए लोन देने में आनाकानी करते हैं। खासकर ऐसे देशों के साथ भारतीय बैंक सौदा नहीं करना चाहते जहां राजनीतिक जोखिम ज्यादा है। लिहाजा ईएक्सआईएम को डिजाइन किया गया है। भारत के एक राजनयिक ने कहा है कि बैंकों की आनाकानी की वजह से भारत को लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंद्वियों जैसे फ्रांस, तुर्की और चीन से पीछे होना पड़ा है, क्योंकि ये देश हथियार खरीदने के लिए भारी भरकम लोन भी देते हैं। लिहाजा भारत भी अब लोन देकर हथियार बेचने के बाजार में आ गया है। भारत ने इस साल जनवरी में ब्राजील में ईएक्सआईएम की एक ब्रांच खोली है। इसके तहत भारत, ब्राजील को मिसाइल बेचने का सौदा कर रहा है। ब्राजील के दो अधिकारियों के मुताबिक भारत, ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। दो भारतीय सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने इस साल साओ पाओलो में दफ्तर खोला है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। बीते 3 साल के दौरान इस जंग में अमेरिका और रूस दोनों ने अपने हथियार झोंके हैं। ऐसे में इन दोनों देशों पर निर्भर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों के पास हथियारों की आपूर्ति के लिए विकल्पों की कमी हो गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मौके को पहचाना और उन देशों से संपर्क बढ़ाया। खास बात यह है कि भारत पश्चिमी और रूसी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता रहा है। भारत के पास दोनों तरह की हथियार टेक्नोलॉजी का अनुभव है। ऐसे में भारत इन देशों की रक्षा जरूरतों को समझ सकता है। एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद स्थिति बदल गई। पश्चिमी देशों ने अपने हथियार यूक्रेन भेज दिए और रूस ने अपने हथियार सिर्फ खुद के लिए बनाए। इससे उन देशों को दिक्कत हुई, जो रूस और अमेरिका पर निर्भर थे ऐसे में वे देश जो दोनों से हथियार खरीदते रहे, उन्होंने भारत से संपर्क करना शुरू किया। भारतीय तोपखाने के कुछ गोले यूक्रेन में भी देखे गए। भारत अब विदेशी डिप्लोमैट्स और अपनी हथियार कंपनियों के बीच बैठकें करा रहा है और सैन्य अभ्यासों में हेलिकॉप्टर जैसे एडवांस्ड हथियार दिखा रहा है। 2023-24 में भारत ने करीब 1.27 लाख करोड़ के हथियार बनाए, जो 2020 की तुलना में 62% ज्यादा है।

यूक्रेन ने चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने पेश किया

रूस की तरफ से जंग लड़ रहे थे; पिछले हफ्ते पकड़ा था

एजेंसी

कीव, यूक्रेन ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने पेश किया। पिछले 3 साल चल रही रूस-यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार हुआ। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ने का दावा किया था। हालांकि, चीन ने अपने नागरिकों के जंग में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया था। इसके बाद यूक्रेन ने इन युद्धबंदियों को मीडिया के सामने परेड कराने का फैसला किया। इसके लिए यूक्रेन ने युद्धबंदी कानून भी तोड़ा है। युद्धबंदियों की पहचान उजागर करना और उन्हें कैमरों व पत्रकारों के सामने पेश करना

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहचान में आए सभी लोगों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी उनके पास है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस सोशल मीडिया के जरिए चीनी नागरिकों की भर्ती कर रहा है। चीन को भी इस बात की जानकारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन यह जानने की कोशिश कर रहा है कि भर्ती करने वालों को बीजिंग की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं या नहीं। इससे पहले जेलेंस्की ने 8 अप्रैल को जंग में शामिल दो चीनी नागरिकों का वीडियो शेयर किया, जिन्हें यूक्रेन ने पकड़ा था। जेलेंस्की ने कहा कि रूस, चीन को इस जंग में खींच रहा है। यह पुतिन के प्लान का हिस्सा है। पुतिन चाहते हैं कि यूरोप में जंग फैले। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क में 6 चीनी नागरिकों से लड़ाई लड़ रही थी। इस दौरान 2 लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। बाकी के चार चीनी नागरिक मारे गए या भाग गए, अभी साफ नहीं है। जेलेंस्की ने दावा किया कि पकड़े गए चीनी नागरिकों के पास से उनके पहचान पत्र, बैंक कार्ड और व्यक्तिगत डेटा मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि चीनी नागरिक अब यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की हिरासत में हैं। जेलेंस्की ने पकड़े गए चीनी नागरिकों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जेलेंस्की ने अगले दिन बुधवार को दावा किया था कि वे रूस में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों के बदले दो युद्धबंदियों को देने को तैयार हैं। जेलेंस्की के दावे को चीन ने खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है।

ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा

कोर्ट ने आरक्षण देने से इनकार किया, कहा- महिला वही जो जन्म से फीमेल

एजेंसी

लंदन, ब्रिटेन में अब ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला होने की कानूनी परिभाषा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो जन्म से महिला यानी बायोलॉजिकल फीमेल है, उसे ही महिला माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से ट्रांसजेंडर अधिकारों पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। कोर्ट ने समानता अधिनियम 2010 की व्याख्या करते हुए बताया कि महिला और लिंग शब्द बायोलॉजिकल फीमेल और बायोलॉजिकल जेंडर को बताते हैं। पांच जजों की बैंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया। बैंच में शामिल जज पैट्रिक हॉज ने कहा कि यह एक्ट ट्रांसजेंडर लोगों को उनके साथ जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव से सरंक्षण देता है। 2018 में स्कॉटलैंड की सरकार ने एक कानून बनाया, जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं में 50% महिलाओं की भागीदारी जरूरी थी। इस कानून में ट्रांसजेंडर महिलाओं (जिनके पास जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट या जीआरसी है) को भी महिला माना गया। फॉर वुमन स्कॉटलैंड नाम के समूह ने इसका विरोध किया और कहा कि यह कानून महिला की परिभाषा को गलत तरीके से बदल रहा है। 2022 में स्कॉटिश कोर्ट में यह मामला हारने के बाद, यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 5 जजों ने एकमत से कहा कि इक्विलिटी एक्ट में महिला और सेक्स का मतलब जन्म से महिला और प्राकृतिक सेक्स है। ट्रांसजेंडर महिलाएं, भले ही उनके पास जीआरसी हो, लेकिन कानूनी रूप से वे महिला की कैटगरी में नहीं आएंगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया, तो कानून अव्यवहारिक हो जाएगा। ट्रांसजेंडर महिलाओं को अब महिलाओं के लिए बने टॉयलेट, चेंजिंग रूम, अस्पताल वार्ड, जेल, या रेप काउंसलिंग सेंटर जैसी जगहों से बाहर रखा जा सकता है। पहले महिलाओं के टॉयलेट या चेंजिंग रूम का ट्रांसजेडर इस्तेमाल कर सकती थीं। अब उन्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए जायज वजह देना होगा। ट्रांसजेंडर को महिलाओं के खेलों से बाहर किया जा सकता है। यह फैसला अमेरिका जैसे देशों में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बहस को प्रभावित कर सकता है, जहां इसे उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांस ब्राडकास्टर और कार्यकर्ता इंडिया विलोबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका दिल टूट गया है। एक महिला के तौर पर मेरे अधिकारों को छीन लिया गया है। मुझे और मेरे जैसे लोगों को यह बताना कि हम महिला नहीं हैं, ऐतिहासिक अन्याय है। विलोबी ने कहा कि ट्रांस-विरोधी लोगों का खुश होना यह साबित करता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। यह फैसला अपमानजनक है। मैं हमेशा एक महिला रही हूं और मैं हमेशा एक महिला ही रहूंगी। हैरी पॉटर की लेखिका जे.के. रोलिंग ने मामले को लेकर एफडब्ल्यूएस का सपोर्ट किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर इस मामले में शामिल सभी महिलाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा- इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए तीन असाधारण महिलाओं की सेना की जरूरत थी और उन्होंने जीत हासिल करके पूरे ब्रिटेन में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा की है।

टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में मोहम्मद यूनुस

ट्रम्प और मस्क ने भी जगह बनाई, पहली बार किसी भारतीय को जगह नहीं

एजेंसी

वॉशिंगटन डीसी, टाइम मैगजीन ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बुधवार को जारी कर दी है। इसमें बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है। हालांकि इस बार लिस्ट में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। पिछले 21 साल के इतिहास में यह पहली बार है। प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कारोबारी इलॉन मस्क को भी जगह मिली है। इस बार ट्रम्प प्रशासन के छह सदस्य लिस्ट में शामिल हैं। ट्रम्प को इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 और 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। 2025 की लिस्ट में मशहूर सिंगर ईडी शिरीन, अमेरिकी एक्टर और सिंगर स्कारलेट जोहानसन, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी शामिल किया गया है। इस साल मैगजीन ने कुल 6 कैटेगरी में 32 देशों के लोगों को शामिल किया गया है। लिस्ट में शामिल 22 साल के फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंड सबसे युवा है, जबकि 84 साल के मोहम्मद यूनुस सबसे बुजुर्ग शख्स हैं। टाइम 100 लिस्ट 2004 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इस लिस्ट को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे लीडर्स, आइकन्स, टाइटन्स, इनोवेटर्स, और आर्टिस्ट्स। हर साल टाइम के एडिटर और एक्सपर्ट्स नामों का चयन करते हैं। पिछले 21 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। इससे पहले 2024 में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 8 भारतीय मूल के लोग शामिल थे, जिनमें आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, सत्या नडेला, अजय बंगा, देव पटेल, जिगर शाह, अस्मा खान, और प्रियंवदा नटराजन का नाम था। इस साल भारतीय मूल की रेशमा केवलरमानी को इस लिस्ट में जगह दी गई है। रेशमा फार्मास्यूटिकल कंपनी वर्टेक्स की सीईओ हैं। केवलरमानी का जन्म मुंबई में हुआ था और वे 1988 में अमेरिका चली गईं। रेशमा 2017 में अमेरिका की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स से जुड़ीं और 1 साल के भीतर ही उन्हें कंपनी का चीफ मेडिकल ऑफिसर बना दिया गया।

सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कर्नाटक कैबिनेट की बैठक

आंतरिक विरोध के बीच जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा

एजेंसी

बढ़ते राजनीतिक तनाव और व्यापक बहस के बीच, कर्नाटक मंत्रिमंडल गुरुवार को विवादास्पद सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट या जाति जनगणना पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित करने वाला है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को आगे की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की उप-समिति या विशेषज्ञ पैनल को भेजने की संभावना पर विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले ही संकेत दे दिया है कि रिपोर्ट पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बहस हो सकती है, सूत्रों ने कहा कि इसे संयुक्त विधायी समिति को भी भेजा जा सकता है। विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का विकल्प भी कथित तौर पर विचाराधीन है।

रिपोर्ट की एक प्रमुख सिफारिश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करना है। कैबिनेट की बैठक के दौरान इस पर चर्चा होने की संभावना है। मौजूदा आंकड़ों में अशुद्धियों के दावों के बीच नए सर्वेक्षण या पुनर्गणना की मांग भी की जा सकती है। रिपोर्ट ने खास तौर पर कर्नाटक के दो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदायों- वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत से काफी विरोध को जन्म दिया है। इन समूहों ने सर्वेक्षण को अवैज्ञानिक करार दिया है और मांग की है कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, इसके बजाय नए और अधिक सटीक गणना की मांग की जाए।इन समुदायों के मंत्रियों से आगामी बैठक में अपना विरोध जताने की उम्मीद है। मुख्य आपत्तियों में से एक यह दावा है कि उनकी उप-जातियों को गलत तरीके से विभिन्न ओबीसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसके कारण कथित तौर पर उनका प्रतिनिधित्व कम हुआ है। उनका यह भी आरोप है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान कई घरों को या तो छोड़ दिया गया या कम गिना गया।

रिपोर्ट की एक प्रमुख सिफारिश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करना है। कैबिनेट की बैठक के दौरान इस पर चर्चा होने की संभावना है। मौजूदा आंकड़ों में अशुद्धियों के दावों के बीच नए सर्वेक्षण या पुनर्गणना की मांग भी की जा सकती है।

अनुच्छेद 370 हटाने का फारूक अब्दुल्ला ने किया था समर्थन

रॉ के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुलत सामने लाये सच्चाई

एजेंसी

मोदी सरकार ने जब साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था तो नेशनल कांफ्रेंस ने बड़ा हो-हल्ला मचाया था। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी गयी थी। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर केंद्र सरकार के इस कदम का समर्थन किया था। इस खुलासे के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में भूचाल आ गया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने से कुछ दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। हम आपको बता दें कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुलत ने अपनी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में जो खुलासे किये हैं, फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा करते हुए इसे ₹विश्वासघात₹ बताया है। फारुक अब्दुल्ला ने दुलत के इस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरोप लगाया कि दुलत अपनी आगामी किताब के प्रचार के लिए इस तरह की सस्ती लोकप्रियताका सहारा ले रहे हैं। अब्दुल्ला ने दुलत के इस दावे को खारिज कर दिया कि यदि नेकां को विश्वास में लिया गया होता तो वह पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित कराने में मदद करती। नेकां अध्यक्ष अब्दुल्ला ने इस पर कहा कि यह लेखक की महज एक कल्पनाहै। हम आपको बता दें कि दुलत की किताब ह्यद चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई का 18 अप्रैल को विमोचन होने वाला है।क्या लिखा है दुलत ने ?हम आपको बता दें कि जगरनॉट द्वारा प्रकाशित किताब के अनुसार, अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला ने दुलत से पूछा था कि हम (प्रस्ताव पारित करने में) मदद करते। हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ?₹ दुलत लिखते हैं कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से कुछ दिन पहले अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ राज्यपाल से की मुलाकात

एजेंसी

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। उन्होंने राज्यपाल से उनकी सुरक्षा, नौकरी और वित्तीय मुआवजे के लिए स्थायी केंद्रीय बल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया। पीड़ित, जो कथित तौर पर हमला किए जाने और अपने घरों से निकाले जाने के बाद राहत शिविर में रह रहे हैं, ने राज्यपाल को बताया कि कैसे उनके सामान लूट लिए गए और घरों, दुकानों और संपत्तियों को आग लगा दी गई, जिससे उन्हें केंद्रीय बलों की मदद से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैं खुद वहां की वास्तविकताओं को देखने के लिए जा रहा हूं...स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। मैं निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद का दौरा करूंगा...क्षेत्र के लोगों ने वहां बीएसएफ कैंप बनाने का अनुरोध किया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद जाऊंगी। मुर्शिदाबाद में अशांति की जांच के लिए एक बीएसएफ का गठन किया गया है।

ये नकली गांधी परिवार खानदानी भ्रष्ट और चोर है

एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गौरव भाटिया ने एक तीखे संबोधन में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पर हमला बोला और उन्हें 'वंशानुगत भ्रष्ट' व्यक्ति करार दिया। यह बयान गुरुग्राम भूमि मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वाड्रा से पूछताछ के बीच आया है। मीडिया को संबोधित करते हुए भाटिया ने वाड्रा को 'भू-माफिया' करार दिया, जिन पर किसानों की जमीनों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप है। इसके अलावा, उन्होंने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड घोटाले, सोनिया गांधी को वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले से जोड़ते हुए उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। भाटिया ने कहा कि एक ईमानदार सरकार की ताकत क्या होती है, ये भारत में अब जनता को पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, किसानों से हड़पी गई जमीन को वापस लेकर किसानों को देंगे। जनता की गाढ़ी कमाई अगर नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाली है, उसकी एक-एक पाई वसूली जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

विविध इलेक्ट्रिकल कार्य

निविदा सं : EL/TRD/Tender/25-26/01 भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) वडोदरा द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। **निविदा सं :** EL/TRD/Tender/25-26/01 **कार्य का नाम :** वडोदरा डिवीजन के सूरत - गोधरा और वडोदरा-गेरतपुर खंड में मौजूदा 1x25 केवी एसी ओएचई सिस्टम को 2x25 केवी एसी ओएचई सिस्टम में परिवर्तित करने के संबंध में आवश्यक फिटिंग के साथ फीडर वायर, एरियल अर्थ कंडक्टर (एईसी) और ब्यूरीड अर्थ कंडक्टर (बीईसी) का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में) :** ₹134608540/- **बोली सुरक्षा (रुपये में) :** ₹823100/- **निविदा दस्तावेजों की लागत और समापन अवधि :** समापन अवधि 18 महीने **निविदा निर्धारित तिथि :** निविदा समापन तिथि 10/05/2025 और समापन का समय उसी तिथि को 12-00 **बजे वेब पेज विवरण और सूचना का लोकेशन जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है तथा कार्यालय का पता विवरण जानकारी के लिए :** मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा - 390 004 **वेब साइट @ www.ireps.gov.in** 009

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

रुचि की अभिव्यक्ति का विज्ञापन

विषयः आर नॉर्थ वार्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत श्रेणी 'डी' में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने के संबंध में।

आर/उत्तर वार्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत डिस्पेंसरी, कार्यालय और श्मशान में स्वैच्छिक संगठनों (बचत समूहों को छोड़कर) के माध्यम से अनुबंध के आधार पर डी" श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए, केवल वे संगठन ही आवेदन करें जिनके पास बृहन्मुंबई महानगरपालिका डिस्पेंसरी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालय और बृहन्मुंबई महानगरपालिका श्मशान में अनुबंध के आधार पर बहुउद्देशीय कर्मचारी उपलब्ध कराने का एक वर्ष का अनुभव हो।

इच्छुक संगठनों में भविष्य निधि राज्य एवं कर्मचारी बीमा योजना में पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियां, सेवा सहकारी समितियां, बेरोजगार सेवा सहकारी समितियां, गैर सरकारी संगठन (इन सभी संगठनों की स्थापना का उद्देश्य अपने सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना होना चाहिए) आदि शामिल हैं। हम संगठनों से उनकी पात्रता सूची तैयार करने और लॉटरी के माध्यम से उनका चयन करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं।

आवेदन पत्र आर उत्तर वार्ड में लोक स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से **19–04–2025 को समय 10,30 से 25–04–205 को समय 4,30 बजे** तक प्राप्त किया जा सकता है।

इच्छुक संगठनों को अधिक जानकारी, आवेदन पत्र और शपथ पत्र के लिए आर नॉर्थ वार्ड स्थित लोक स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

संगठन के आवेदन की अंतिम तिथि 25–04–2025 जपउम 4.30चद है। निर्दिष्ट कार्यालय समय के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर
स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी,
आर/एन वार्ड

पीआरओ/164/विज्ञा0/2025-26

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं

संक्षेप

तीन महिलाओं के यौन शोषण का केस ट्रांसफर

आरोपियों की जमानत याचिका एससी-एसटी कोर्ट में होगी सुनवाई, 23 अप्रैल को लगी डेट

बांदा,तीन महिलाओं के यौन शोषण मामले में नया मोड़ आया है। स्पेशल सेशन कोर्ट ने लोकेंद्र सिंह और स्वतंत्र साहू की जमानत याचिका को एससी-एसटी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने मुकदमा विवेचक को पीड़िता को सम्मन तामील करने और जमानत याचिका पर अपनी राय देने का आदेश दिया है। मामला 22 मार्च को दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर दलाल नवीन विश्वकर्मा और आरोपी लोकेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। अन्य दो आरोपी स्वतंत्र साहू और आशीष अग्रवाल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सभी आरोपी बांदा के प्रमुख व्यवसायी हैं। तीन युवतियां नौकरी की तलाश में इनके पास गई थीं। आरोपियों ने नौकरी देने का झांसा देकर तीन महीने तक उनका यौन शोषण किया। परेशान होकर पीड़िताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को 23 अप्रैल तक हर हाल में सम्मन तामील करने के विशेष निर्देश दिए हैं।

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट का विरोध

बांदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट तक मार्च, बोले- सरकार डरी है

बांदा, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में उत्तर प्रदेश के बांदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अशोक लाट से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके हाथों में विरोध प्रदर्शन के बैनर थे। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष से डरी हुई है। इसलिए वह ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बोले- जेल जाने को भी तैयार जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी किसी भी एजेंसी की दमनकारी कार्रवाई से नहीं डरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने दमन की यह नीति जारी रखी, तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जेल जाने को भी तैयार हैं।

परिवहन और खनिज विभाग ने 12 ट्रक को किया सीज

14 का चालान; डीएम के निर्देश पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई

बांदा, बांदा में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी जे. रीभा के निर्देश पर संभागीय परिवहन विभाग और जिला खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में टीम ने ओवरलोड 12 ट्रकों को सीज किया। साथ ही 14 वाहनों का चालान भी काटा गया। जांच में सामने आया कि अधिकतर ट्रक अनफिट थे। इनमें बॉडी अवैध रूप से बढ़ाई गई थी। कई वाहनों का बीमा और टैक्स भी जमा नहीं था।

साथी को थाने में पीटा, वकीलों का हंगामा

थाने में रात से बंद था अधिवक्ता, कई वकीलों ने बैठकर दिया धरना

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज, कचहरी के वकील आदर्शन मिश्र को थाने में बैठाकर पीटने के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यमुनापार के औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे दर्जनों वकीलों ने हंगामा कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए वकील थाने में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि वकील को पुलिसवालों ने इतना पीटा कि वह अधमरा हो गए। वकीलों के पहुंचने पर उन्हें थाने से हटा दिया गया। थाने के अंदर हंगामे और धरना दिए जाने से अफरातफरी मच गई। पुलिस का कहना है कि वकील को मेडिकल के लिए भेजा गया है। वकीलों ने पूरे मामले को आला अफसरों के संज्ञान में दिया है। एडीए कालोनी नैनी के रहने वाले श्याम मिश्र के बेटे आदर्श मिश्र जिला अदालत में वकालत करते हैं। रात में करीब 11 बजे वह अपनी कार से जा रहे थे। रात में ट्रकों की लाइन लगी थी। इसी बीच एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दिया। इसके बाद आदर्श और ट्रक चालक में मारपीट हो गई। औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस पहुंची और सभी को थाने ले गई। वकीलों का आरोप है कि ट्रक ड्राइवर से तहरीर लेकर आदर्श के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उन्हें थाने में बैठाकर पीटा गया। पूरी रात थाने में बंद रखा गया। इसी मामले को लेकर दोपहर में वकील थाने पहुंच गए और हंगामा कर दिया। थाने पहुंचे वकीलों में रत्नेश शुक्ला, रोहित पांडेय, राहुल पांडेय, अशीष कनौजिया, आलोक मिश्र, हर्ष शुक्ला आदि ने जमकर विरोध जताया।

नैनी में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर

बाइक सवार महिला की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हाईवे जाम

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज , नैनी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टीडीआई राजपूत ढाबे के पास नए पुल पर रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान घूरपुर तातारगंज की रहने वाली शिवकली के रूप में हुई। वह अपने पति शिव प्रसाद के साथ डांडी के एक निजी अस्पताल से दवा लेकर लौट रही थी। जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि शिवकली सड़क पर गिर गई और उनकी मौत हो गई। हादसे में उनके पति शिव प्रसाद को कोई चोट नहीं आई।

घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

आवासीय क्षेत्र में घायल मिला हिरण

कुत्तों के हमले से जख्मी जानवर का इलाज शुरू, वन विभाग मौके पर पहुंचा

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अमेठी जिला, जामो थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में आज सुबह एक अजीब घटना सामने आई। कुत्तों के हमले से घायल एक हिरण रिहायशी इलाके में पहुंच गया। हिरण को सबसे पहले गांव निवासी नरेंद्र बहादुर सिंह के घर के पास देखा गया। घायल हिरण को देखते ही गांव में हलचल मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही वन दरोगा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने हिरण के इलाज के लिए पशु विभाग को भी सूचना दी। पशु विभाग की टीम तत्काल गांव के लिए रवाना हो गई। वन दरोगा ने बताया कि पशु चिकित्सक घायल हिरण का इलाज करेंगे। वन विभाग की टीम रख रही नजर हिरण की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर हिरण की स्थिति में सुधार होता है, तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यदि स्थिति गंभीर रही तो उसे वन विभाग की देखरेख में रखा जाएगा। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

बीसी सखी बहनों की समस्या

यूपीआईकॉन कंपनी पर वसूली का आरोप, डिवाइस कर दी जा रही लॉक

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

सुलतानपुर, बीसी सखी बहनों ने डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है। इसमें यूपीआईकॉन कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 'वन जीपी वन बीसी' के तहत बीसी सखी बहनों को कंपनी द्वारा डिवाइस दी गई थी। शुरूआत में डिवाइस एलडी मोड पर काम कर रही थी। बाद में कंपनी ने बताया कि अब डिवाइस एल1 मोड पर चलेगी। बहनों ने एल1 डिवाइस भी ले ली, जो शुरू में ठीक चल रही थी। लेकिन कंपनी ने अचानक डिवाइस को लॉक कर दिया। अब कंपनी बहनों पर 6,000 रुपये की नई एल1 डिवाइस खरीदने का दबाव बना रही है। पहले ही बहनों से 31,190 रुपये लिए जा चुके हैं। इसके अलावा रिचार्ज के नाम पर 236 रुपये की अतिरिक्त वसूली की जा रही है। एक घंटे भी सही से नहीं चल रही बीसी सखियों का कहना है कि 6,000 रुपये की नई डिवाइस भी ठीक से काम नहीं कर रही। यह एक घंटे भी लगातार नहीं चलती। बाजार में यही डिवाइस आधे दाम में उपलब्ध है। कंपनी की इन कार्रवाइयों से बहनों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सुनीता, आशा चतुर्वेदी, कुसुम कुमारी समेत 25 से अधिक बीसी सखी बहनों ने जिलाधिकारी से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत

अमेठी में टांडा-बांदा राजमार्ग पर हादसा, चालक हिरासत में, ट्रक जब्त

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अमेठी जिला, टांडा-बांदा राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। प्रधान ढाबा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गौरीगंज पुलिस ने घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। वह फुरसतगंज थाना क्षेत्र के पुरे ब्रह्मा का रहने वाला था। राजेंद्र प्रसाद महादेव का पुत्र था। हादसे में शामिल वाहनों में ट्रक की संख्या यूपी 36अळ 3040 और मोटरसाइकिल की संख्या यूपी 33 एएम 8895 है। पुलिस ने ट्रक चालक को गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया है। मृतक के परिजनों को शव की शिनाख्त के लिए सूचना दे दी गई है। पुलिस शव का पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

किसानों की मासिक बैठक

फसल नुकसान, आवारा पशु और बिजली बिल की परेशानी, डीएम को दिया मांग पत्र

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

सुलतानपुर, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक बैठक गुरुवार को तिकोनिया पार्क में आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। ओलावृष्टि और बरसात से हुए फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को राहत दिलाने पर जोर दिया गया। जिले की गोशालाओं में पशुओं की खराब व्यवस्था का मुद्दा भी उठा। किसानों ने सभी तहसीलों में स्थित उपनिबंधक कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की जांच की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में पानी की व्यवस्था करने की मांग भी रखी गई। शारदा सहायक खंड-16 की माइनरों और कुलाबों की खराब स्थिति से सिंचाई में हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया गया। बढ़ते अपराधों पर जताई चिंता विद्युत विभाग द्वारा गलत मीटर रीडिंग के कारण आ रहे भारी बिलों की शिकायत की गई। जिले में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई गई। संगठन ने कई बार जिलाधिकारी से वार्ता का आग्रह किया, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई है। किसान नेताओं ने जल्द से जल्द वार्ता की तिथि तय करने की मांग की है।

गभाना टोल पर कर्मचारियों से मारपीट

भीम आर्मी वाले बिना टोल दिए गाड़ी ले जाना चाहते थे, रोकने पर किया हंगामा

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अलीगढ़, गभाना थाना क्षेत्र के गभाना टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि भीम आर्मी के लोगों ने टोल न देने के लिए जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं आरोपियों ने महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता और बदसलूकी भी की है। जिसके बाद टोल मैनेजर की ओर से गभाना थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। टोल के कर्मचारी सुमित सिंह की ओर से पुलिस को तहरीर देकर बताया गया है कि गुरुवार दोपहर लगभग 11:25 पर 10-15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यह लोग खुद को भीम आर्मी संगठन के पदाधिकारी बता रहे थे और बिना टोल दिए गाड़ी निकालने का दबाव बना रहे थे। जब कर्मचारियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपी मारपीट पर हो गए और महिला कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी की। संगठन की आड़ में 50-60 लोगों की भीड़ एकदम से टोल पर टूट पड़ी और जमकर हंगामा और मारपीट की। महिला कर्मचारियों ने जैसे-तैसे खुद को बचाया। आरोपियों ने राजस्व की हानि भी की। टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट और हंगामे का सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। जिसके बाद यह फुटेज जमकर वायरल हो रहे हैं और कर्मचारियों ने पुलिस को भी सीसीटीवी उपलब्ध कराए हैं। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सीओ गभाना संजीव तोमर ने बताया कि टोल कर्मचारियों की ओर से तहरीर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लोग आरोपी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

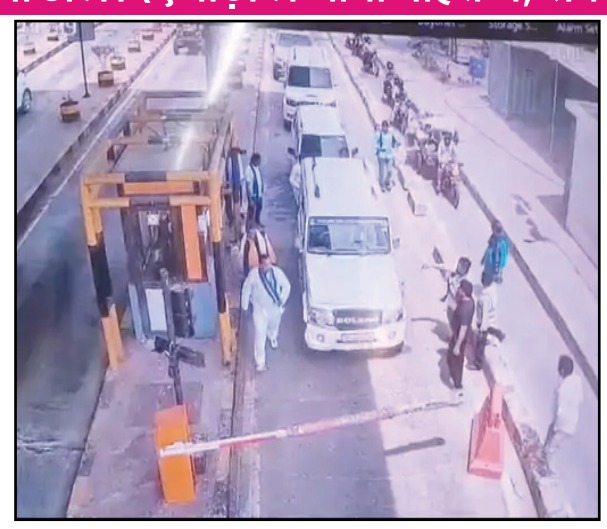

बाल विवाह रोकने के लिए स्कूल की विशेष पहल

जायस के इंटर कॉलेज में चलाया जागरूकता अभियान, 1098 हेल्पलाइन की जानकारी दी

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अमेठी जिला, जायस स्थित मलिक मोहम्मद भारती इंटर कॉलेज में बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यह अपराध है। दोषी को 2 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुमार्ना हो सकता है। कार्यक्रम में बताया गया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव भी पैदा होता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामकुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम सफल रहा। सहायक अध्यापक सुनील कुमार, शिल्पी श्रीवास्तव और बबीता गुप्ता ने भी सहयोग दिया।

गेहूं कटाई के दौरान हादसा

कंबाइन मशीन पलटने से चालक समेत 3 लोग घायल, सभी खतरे से बाहर

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अमेठी जिला, अमेठी में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पूरे प्रेम शाह गांव में गेहूं की कटाई के दौरान कंबाइन मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। इनमें कंबाइन मशीन का चालक प्रेमराज (30 वर्ष), अंबुज यादव (18 वर्ष) और शिवम यादव शामिल हैं। प्रेमराज शाहजहांपुर का रहने वाला है। अंबुज यादव निजामुद्दीनपुर और शिवम यादव पूरे टिकरा बैजनाथ के निवासी हैं। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने घायलों को निजी वाहन से मुसाफिरखाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। वर्तमान में सभी घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।

नए बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों में हाथापाई

सवारी को लेकर दो अनुबंधित बसों के स्टाफ में मारपीट

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मथुरा, नए बस स्टैंड पर गुरुवार को सवारियों को बिठाने के विवाद में रोडवेज की दो अनुबंधित बसों के कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दो लोग घायल हो गए। घटना में दोनों बसों के चालक और परिचालक आमने-सामने आ गए। एक युवक ने रोडवेज कर्मचारी पर लगातार लात-घूंसे बरसाए। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट घटना को देख बस स्टैंड पर मौजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मैं लोगों ने बीच बचाव किया लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करने के लिए उतारू थे। बताया गया कि इस मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। इसके बाद यह मामला स्थानीय थाने तक पहुंच गया। शहर कोतवाली की चौकी प्रभारी मांगेराम ने बताया कि नए बस स्टैंड पर रोडवेज की दो अनुबंधित बसों के स्टाफ कर्मचारी अजीत,सीताराम, राम, और राकेश में आपस में मारपीट हुई है

स्वामी, प्रकाशक , मुद्रक अरविंद कुमार शर्मा द्वारा एफ एल टी ,एलजी 75 आर एम 4/4 इंदिरा नगर, सुंदर बाग,कुर्ला (प)मुंबई 400070 महाराष्ट्र से प्रकाशित एवं AIS PRINTING SOLUTION प्लांट नं० -A-544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एम आई डीसी माहपे नवी मुंबई ,ठाणे 400709 से मुद्रित। संपादक - अरविंद कुमार शर्मा

EMail-bsmumbai2017@gmail.com किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र मुम्बई न्यायालय ही होगा। 8097049935,9935750291RNI No-MAHHIN2017/74173

संपर्क का कार्यालय- 66/68 भाखरिया बिल्डिंग मीना मेहता मार्ग मोदी स्ट्रीट मुम्बई 400001

संरक्षक- डॉ राम किशोर शर्मा पूर्व विभागाध्यक्ष (हिन्दी) इलाहाबाद विश्व विद्यालय, विशेष संवाददाता- आशीष कुमार शर्मा सह, सम्पादक- माता प्रसाद शर्मा, फिल्म- संपादक-जगन्नाथ तिवारी